

[2023] 5 एस. सी. आर 949

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

बी.

डीलोइट हैस्कन और एलएलपी और ए. एन. आर. बेचता है।

(2022 की आपराधिक अपील Nos.2305-2307)

03 मई, 2023

[एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.140 (5)-का विश्लेषण और व्याख्या-यू/के तहत कार्यवाही की रखरखाव क्षमता s.140 (5) के इस्तीफे के बाद लेखा परीक्षक - s.140 (5) न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को, या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या केंद्र सरकार द्वारा या किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, लेखा परीक्षक के खिलाफ कार्यवाई करने का अधिकार देता है जो

यदि किसी जांच के पूरा होने पर न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की है, तो वह आदेश द्वारा कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश दे सकता है-विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार लेखा परीक्षक ने लेखा परीक्षक के रूप में इस्तीफा दे दिया है या अपने इस्तीफे पर लेखा परीक्षक नहीं है। 140 (5) कार्यवाही अब बनाए रखने योग्य नहीं है-चाहे लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बाद, कार्यवाही यू/एस। 140 (5) रखरखाव योग्य हैं-आयोजित: द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

उच्च न्यायालय पूरी तरह से गलत है और अस्थिर है-आवेदन/कार्यवाही यू / अधिनियम, 2013 का s.140 (5) रखरखाव योग्य है।

एस के पहले भाग के तहत शुरू की गई संबंधित लेखा परीक्षकों की पूछताछ/कार्यवाही के इस्तीफे के बाद भी। 140 (5) अपने तार्किक अंत और बाद में इस्तीफे और/या बंद करने के लिए जाना है लेखा परीक्षक जांच/कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगा। 140 (5) - यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या कि एक बार लेखा परीक्षक के इस्तीफा देने के बाद, यू/एस के तहत कार्यवाही की जाती है। 140 (5) उस मामले में, अंतिम आदेश और अंतिम आदेश के परिणाम से बचने के लिए एक लेखा परीक्षक को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि एस के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किया गया है। 140 (5) न्यायाधिकरण इस्तीफा दे सकता है और किसी भी अंतिम आदेश से बच सकता है-यह विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है-एन. सी. एल. टी. कानून के अनुसार जांच करने के बाद और उसके बाद ऐसे अंतिम आदेश के आधार पर ऐसे आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करने के लिए,

[2023] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस के लिए दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए आगे के परिणाम। 140 (5) इसका पालन करेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.140 (5)-की संवैधानिक वैधता - s.140 (5) न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या केंद्र सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर अधिकार देता है।

संबंधित, उस लेखा परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करना जिसने धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या किसी कंपनी के प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की है-यदि जांच पूरी होने पर

न्यायाधिकरण द्वारा पाया गया कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या उसे उकसाया है या उकसाया है।

कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में मिलीभगत से, यह आदेश द्वारा कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश दे सकता है-धारित: s.140 (5) न तो भेदभावपूर्ण, मनमाना और/या कला का उल्लंघन करने वाला है। 14 , 19 (1) (छ) संविधान का-एन. सी. एल. टी. अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। 140 (5) दीवानी न्यायालय के समान सभी शक्तियों के साथ -

किसी भी अंतिम आदेश याचिका को पारित करने से पहले एन. सी. एल. टी. द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाता है। 140 (5) समान रूप से रखे गए कथित अपराधियों की तुलना में लेखा परीक्षकों के साथ अनुचित तरीके से भेदभाव करता है, जैसे कि

निदेशक, प्रबंधन आदि मान्य नहीं हैं, क्योंकि लेखा परीक्षकों की भूमिका की तुलना निदेशकों और/या प्रबंधन के साथ नहीं की जा सकती है।

एक लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी का तरीका एक बहुत ही गंभीर दुराचार है और इसलिए इसका आवश्यक परिणाम है -

इस तरह के धोखाधड़ी वाले कार्य में लिप्त होने का पालन किया जाएगा-केवल इसलिए कि

लेखा परीक्षक को कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में हटाया जा सकता है

अन्य प्रावधान, s.140 (5) जिसे एक विशेष उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है, उसे मनमाना और/या अधिकार से परे नहीं कहा जा सकता है।

भारत का संविधान-कला। 14 और 19 (1) (जी)।

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.140 (5), पहला परंतुक-एस के पहले परंतुक के तहत शक्तियाँ। 140 (5) - आयोजित की प्रकृति: कहा जा सकता है कि एक मौजूदा लेखा परीक्षक को रोकने के लिए अंतरिम या अस्थायी उपाय

उसे जारी रखें और एक प्रथम आधार पर एक लेखा परीक्षक के साथ प्रतिस्थापित करें

प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि कि धोखाधड़ी की गई है और कब परिस्थितियां प्रतिस्थापन की गारंटी देती हैं-इस तरह के आदेश को अस्थायी निलंबन के समान एक अंतरिम आदेश कहा जा सकता है।

एस में दी गई विस्तृत जांच की विचाराधीनता। 140 (5) और इससे पहले कि न्यायाधिकरण द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित किया जाए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.140 (5), दूसरा परंतुक-उद्देश्य और उद्देश्य-जब आकर्षित किया जाता है:

भारत और एक अन्य संघ का उद्देश्य और उद्देश्य V. डिलोइट हैस्कन और एलएलपी बेचता है

एस के लिए दूसरा परंतुक। 140 (5) प्रावधान को और अधिक कठोर बनाना और एक लेखा परीक्षक के लिए परिणाम प्रदान करना है जब ऐसा लेखा परीक्षक हो।

एस के पहले भाग के अनुसार। 140 (5) और एन. सी. एल. टी. द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी के तरीके से कार्य किया या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की।

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.140 (5)-न्यायाधिकरण यू/एस को प्रदत्त शक्तियाँ। 140 (5) - यदि अधिनियम, 2013 या तत्काल लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-आयोजित किया गया: अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद,

2013 , न्यायाधिकरण के पास यू/एस की शक्तियाँ निहित हैं। 140 (5) फाइनल पास करने के लिए

उच्च न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) नतीजतन एस. एफ. आई. ओ. द्वारा दायर अभियोजन को दरकिनार कर दिया गया-उच्च न्यायालय

एस को अलग रखें। 212 (14) मुख्य रूप से दो आधारों पर निर्देश, पहला, कि मुकदमा चलाने का निर्देश रिपोर्ट के 30 घंटे के भीतर जारी किया गया था

एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट जो विवेक के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाती है और दूसरा इस आधार पर कि एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट एक अधूरी रिपोर्ट थी क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई थी और इसलिए एस. 212 (14) निर्देशन अक्षम था-आयोजित: केवल इसलिए कि मुकदमा चलाने का निर्देश 30 घंटों के भीतर जारी किया गया था, उसके द्वारा ही यह नहीं माना जा सकता है कि दिमाग का कोई उपयोग नहीं था-जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि मुकदमा चलाने के लिए कोई सामग्री थी या नहीं और मुकदमा चलाने का निर्देश ठीक से दिया गया था या नहीं-उच्च न्यायालय ने यह भी ठीक से नहीं माना कि एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट आई. एफ. आई. एन. की जांच पूरी होने पर तैयार की गई एक रिपोर्ट थी-जांच के तहत कंपनियों में से एक-आई. एफ. आई. एन. आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की सहायक कंपनियों में से एक थी और वित्तीय सेवा शाखा केवल इसलिए थी क्योंकि अन्य सहायक कंपनियों के संबंध में जांच की गई थी।

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह की कंपनियाँ चल रही होंगी, यह देखने का आधार नहीं हो सकता है कि जहां तक आई. एफ. आई. एन. का संबंध है, रिपोर्ट अधूरी थी-उच्च न्यायालय ने [2023] 5 एस. सी. आर. में उस जांच को भौतिक रूप से गलत बताया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. एफ. आई. एन. का सम्मान अधूरा था-उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही निर्देश के चरण में थी s.212 (14) अभियोजन पक्ष को अनुमति देने और अभियोजन की मंजूरी देने के लिए-संबंधित अभियुक्त के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध था-इसलिए, उच्च न्यायालय ने यू / s.212 (14)।

कंपनी अधिनियम, 2013-अध्याय X-लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक

-

आयोजित किया गया: लेखा परीक्षकों की भूमिका की तुलना निदेशकों और/या निदेशकों के साथ नहीं की जा सकती है।

प्रबंधन।

शब्द और वाक्यांश-दूसरे परंतुक में उपयोग किया जाने वाला शब्द "कोई भी"

एस. 140 (5) अधिनियम, 2013 का-अर्थ-एस के दूसरे परंतुक के तहत। 140 (5) , न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने पर कि लेखा परीक्षक/फर्म ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की है, वह पांच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा-अभिनिर्धारित किया गया:

"कोई भी" शब्द महत्वपूर्ण है-न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने पर, ऐसे लेखा परीक्षक को न केवल किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में हटा दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा, बल्कि ऐसा लेखा परीक्षक/फर्म भी पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। s.140 (5)।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1 . धारा के पहले भाग में एन. सी. एल. टी. की शक्तियाँ

140 (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रकृति अर्ध-न्यायिक है और न्यायाधिकरण के पास जांच करने के लिए दीवानी अदालत की शक्तियाँ होंगी।

लेखा परीक्षकों की भूमिका और उनके धोखाधड़ीपूर्ण आचरण और उनके कार्य के त्याग पर निर्णय लेना। धारा 140 (5) के पहले परंतुक के तहत शक्तियों को अंतरिम या अस्थायी उपाय कहा जा सकता है ताकि मौजूदा लेखा परीक्षक को उसे जारी रखने और प्रतिस्थापित करने से रोका जा सके।

एक प्रथम दृष्टया संतुष्टि के आधार पर एक लेखा परीक्षक के साथ कि एक धोखाधड़ी की गई है और जब परिस्थितियाँ वारंट करती हैं प्रतिस्थापन। इस तरह के आदेश को विचाराधीनता के दौरान अस्थायी निलंबन के समान एक अंतरिम आदेश कहा जा सकता है।

अधिनियम की धारा 140 (5) में प्रदान की गई विस्तृत जांच और न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से पहले। [पैरा 5.2] [1005 डी-जी]

2. इस प्रकार, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक को कहा जा सकता है:

यह एक मूल प्रावधान होगा और यह भारत और ए. एन. डी. ए. वी. के अंतिम क्रम पर काम करता है।

डीलोइट हैस्कन और एलएलपी बेचता है

न्यायाधिकरण द्वारा धारा 140 (5) (प्रथम भाग) के तहत पारित किया गया। धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक विस्तृत विश्लेषण के बाद और निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रस्तुत किया गया था:

धोखाधड़ी करना और ऐसी धोखाधड़ी के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा उसे हटा दिया जाता है। एन. सी. एल. टी. द्वारा धारा 140 (5) के पहले भाग के तहत अंतिम आदेश पारित होने पर और यदि कोई लेखा परीक्षक धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या कंपनी के प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है, तो धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए परिणाम अनुसरण करेंगे। इसलिए, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक को आकर्षित करने से पहले, पहले के अनुसार कंपनी के लेखा परीक्षक के खिलाफ एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। धारा 140 (5) का हिस्सा और एन. सी. एल. टी. द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की है।

कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में। [पैरा 5.3] [1006-ए-जी]

3. धारा 140 (5) के तहत आवेदन दायर किए जाने के बाद किसी लेखा परीक्षक का बाद में इस्तीफा अपने आप में इस पद को समाप्त नहीं करेगा - धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही। लेखा परीक्षक के इस्तीफे और/या हटाने को धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही का अंत नहीं कहा जा सकता है। इसके और भी परिणाम हैं

धारा 140 (5) कार्यवाही के तहत जांच की पराकाष्ठा और एक लेखा परीक्षक के आचरण पर न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित करना, चाहे ऐसे लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया हो या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की हो, जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, धारा 140 (5) के पहले भाग के तहत शुरू की गई जांच/कार्यवाहियों को अपने तार्किक अंत तक जाना होगा और बाद में एक लेखा परीक्षक का इस्तीफा और/या बंद करना धारा 140 (5) के तहत जांच/कार्यवाहियों को समाप्त नहीं करेगा। अगर

उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या कि एक बार लेखा परीक्षक के इस्तीफा देने के बाद, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है और उस मामले में, अंतिम आदेश और अंतिम आदेश के परिणाम से बचने के लिए एक लेखा परीक्षक को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है।

धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत दिया गया आदेश

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस्तीफा दे सकते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी अंतिम आदेश से बच सकते हैं। विधायिका का इरादा ऐसा नहीं हो सकता। [पैरा 6] [1007-ए-डी]

4. अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक एक ठोस प्रावधान है, हालांकि यह एक परंतुक के रूप में है और

5. अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की सही व्याख्या और योजना पर, एक बार जब अधिनियम की धारा 140 (5) के पहले भाग के तहत जांच/कार्यवाही शुरू की जाती है, तो या तो न्यायाधिकरण द्वारा या केंद्र द्वारा किए गए आवेदन पर। सरकार या किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा, इसे अपने तार्किक अंत तक आना चाहिए और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि भारत के इस तरह के संघ के दौरान और एक और VI

डीलोइट हैस्कन और एलएलपी बेचता है

लेखा परीक्षक ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं, इसकी जांच/कार्यवाही के लिए न्यायाधिकरण द्वारा एक अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे लेखा परीक्षक ने वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या नहीं। कंपनी को धारा 140 (5) के पहले भाग में दिए गए अपने लेखा परीक्षक को बदलने का निर्देश केवल न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का परिणाम है कि लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है। यह पहला है। धारा 140 (5) (प्रथम भाग) के अधीन अंतिम आदेश का परिणाम। न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी से काम किया है,

धारा 140 (5) आकर्षित की जाएगी। इसलिए, किसी भी परिणाम के लिए धारा 140 (5) के दूसरे परन्तुक के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार, पहले भाग के अनुसार जांच पर न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश होगा।

धारा 140 (5)। इसलिए, सही व्याख्या पर, धारा 140 (5) के तहत जांच/कार्यवाही के दौरान या उससे पहले भी किसी कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा इस्तीफे पर भी, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही की कोई समाप्ति नहीं होगी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया था। किसी मामले में, एक लेखा परीक्षक, जिसने वास्तव में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक मामले में कार्य किया है

धोखाधड़ी के तरीके से, धारा 140 (5) के दूसरे परन्तुक के तहत किसी भी आगे के परिणाम से बचने के लिए, धारा 140 (5) के दूसरे परन्तुक के तहत किसी भी परिणाम से बचने के लिए इस्तीफा दे सकता है।

अनुमति दी जाए। [पैरा 7] [1008-सी-जी]

6.1 . जहाँ तक यह निवेदन है कि भले ही धारा 140 (5) न होती, उस मामले में भी कोई लेखा परीक्षक ऐसा नहीं कर सकता है।

धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के लिए उकसाने या पेशेवर कदाचार आदि और उस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 132,141,147,245 और 447 पर निर्भरता का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त सभी प्रावधान और धारा 140 (5) काम करते हैं।

अलग-अलग क्षेत्रों में। केवल इसलिए कि लेखा परीक्षक को अन्य प्रावधानों सहित किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में हटाया जा सकता है, धारा 140 (5) जिसे एक विशेष उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है।

इसे मनमाना और/या अति अधिकार नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 8] [1008 एच; 1009-ए, बी-सी]

6.2 . अधिनियम, 2013 की योजना के अनुसार, विशेष रूप से अध्याय X के अनुसार, लेखा परीक्षक एक स्वतंत्र परीक्षक के रूप में कार्य करता है

खाते और आचरण [2023] 5 एस. सी. आर. में एक पद धारण करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और कंपनी का प्रबंधन। अतः यह निवेदन कि

अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत जो हासिल किया जा सकता है, वह धारा 241 (3) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, भले ही लेखा परीक्षक ने इस्तीफा दे दिया हो। [पैरा 9] [1009-जी-एच]

6.3 . धारा 140 (5) में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि "इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

या उस समय लागू कोई अन्य कानून। इसलिए, धारा 140 (5) को अधिनियमित करते समय विधायिका का इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 140 (5) के तहत न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियां कंपनी अधिनियम, 2013 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी। इसलिए, किसी भी अन्य के बावजूद

अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत इस आरोप पर लेखा परीक्षक के खिलाफ अंतिम आदेश पारित करने की शक्तियां निहित हैं कि कंपनी के ऐसे लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी से काम किया है। [पैरा 10] [1010 ए-सी]

7. धारा 140 (5) को अत्यधिक और/या स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि तर्क दिया गया है। यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से संवैधानिकता/अधिकारों पर मामला था।

धारा 140 (5) कि धारा 140 (5) अत्यधिक और मनमाना है क्योंकि यह एन. सी. एल. टी. को इसके लिए निर्देशित और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान करती है।

धोखाधड़ी के गंभीर अपराध का निर्धारण और इसके परिणाम

सिविल मृत्यु के समान गंभीर परिणामों के साथ अनिवार्य अयोग्यता। उपरोक्त में कोई सार नहीं है। एन. सी. एल. टी. दीवानी अदालत के समान सभी शक्तियों के साथ धारा 140 (5) के तहत अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले एन. सी. एल. टी. द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। [पैरा 12] [1011-ए-सी]

8. जहाँ तक यह निवेदन है कि धारा 140 (5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसके खिलाफ भेदभाव करती है।

समान रूप से रखे गए कथित की तुलना में लेखा परीक्षकों ने अनुचित तरीके से

निदेशकों, प्रबंधन आदि जैसे अपराधियों के संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लेखा परीक्षकों की भूमिका को निदेशकों और/या प्रबंधन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लेखा परीक्षक कंपनी के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए उन्हें व्यापक सार्वजनिक हित में और निवेशकों आदि सहित अन्य सभी हितधारकों के लिए कार्य करना पड़ता है। अधिनियम का अध्याय X विशेष रूप से लेखा परीक्षकों के महत्व को देखते हुए "लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों" के लिए है।

भारत संघ और एक अन्य V. डीलोइट हैस्कन और एलएलपी बेचता है

इसलिए, धारा 140 (5) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और/या उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 13] [1011-सी-ई]

9. यह प्रस्तुत किया गया था कि लेखा परीक्षकों और भागीदारों सहित पूरी फर्म की स्वतः अयोग्यता के रूप में जुर्माना और वह भी किसी अन्य कंपनी का लेखा परीक्षक बनने के लिए पांच साल की अवधि के लिए अत्यधिक असमान है। हालांकि यह

अंततः विधायिका/संसद को प्रतिबंध प्रदान करने के लिए। संयुक्त और गंभीर दायित्व के सिद्धांत पर, लेखा परीक्षक और भागीदारों सहित पूरी फर्म उत्तरदायी होगी और इसलिए धारा 140 (5) और अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) में उल्लिखित परिणामों के अधीन हो सकती है। किसी को भी यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी से काम करने के बावजूद, उन्हें अपने पेशे को जारी रखने और/या जारी रखने का अधिकार था। एक लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी से कार्य करना एक बहुत ही गंभीर दुराचार है और इसलिए इसका आवश्यक परिणाम है - इस तरह के धोखाधड़ी के कृत्य में शामिल होने का पालन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 140 (5) को विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है

और इसे उचित विचार-विमर्श के बाद और स्थायी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है

समिति के साथ-साथ संबंधित हितधारक भी। इसलिए, उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए अधिनियम की धारा 140 (5) को अधिनियमित किया गया है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना, अत्यधिक और उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है।

और/या अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

19 (1) (छ) भारत के संविधान का, जैसा कि आरोप लगाया गया है। [पैरा 14] [1011 ई-एच; 1012-ए-सी]

10.1 . उच्च न्यायालय ने धारा 212 (14) के तहत दिए गए निर्देश को दरकिनार करते हुए इसे विवेक का उपयोग न करने के रूप में कहा क्योंकि यह असंभव था कि लगभग 750 पृष्ठों और 32000 पृष्ठों की रिपोर्ट

अनुलग्नक पर 30 घंटे में विचार किया जा सकता था। द. टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बस।

उच्च न्यायालय द्वारा की गई

क्योंकि मुकदमा चलाने का निर्देश 30 घंटे के भीतर जारी किया गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि दिमाग का उपयोग नहीं किया गया था। अधिकारी द्वारा एक विस्तृत नोट तैयार किया गया था जिसे अंततः अंतिम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था जो

अंततः एक निर्णय लिया और मुकदमा चलाने का निर्देश जारी किया। इस पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या कोई [2023] 5 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमा चलाने के लिए सामग्री या नहीं और क्या मुकदमा चलाने का निर्देश ठीक से दिया गया था या नहीं। मुकदमे के दौरान आरोपी

उन्हें अपना मामला रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। इसलिए, उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय ने इसके तहत जारी अभियोजन के निर्देश को रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

अधिनियम की धारा 212 (14)। [पैरा 15.1 और 15.2] [1012-एफ-एच; 1013 ए-बी]

10.2 . उच्च न्यायालय ने ठीक से इस बात की सराहना नहीं की है कि एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट एक रिपोर्ट थी जिसे पूरा होने पर तैयार किया गया था।

आई. एफ. आई. एन. की जाँच-जाँच के अधीन कंपनियों में से एक। आई. एफ. आई. एन. आई. एल. एंड एफ. एस. समूह और वित्तीय सेवा शाखा की सहायक कंपनियों में से एक थी। केवल इसलिए कि जहां तक आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह की अन्य सहायक कंपनियों के संबंध में जांच का संबंध है, वही चल रहा होगा, यह देखने का आधार नहीं हो सकता है कि इस स्तर पर जहां तक आई. एफ. आई. एन. का संबंध है, रिपोर्ट अधूरी थी और जिसके लिए जांच चल रही थी। उच्च न्यायालय ने भौतिक रूप से गलती की कि आई. एफ. आई. एन. के संबंध में जांच अधूरी है। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही धारा 212 (14) के तहत अभियोजन की अनुमति देने और मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के निर्देश के चरण में थी। के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे

संबंधित अभियुक्त जिनके खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 और आई. पी. सी. के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन का आदेश दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने धारा के तहत निर्देश को दरकिनार करने में गलती की है

212 (14) . [पैरा 15.3] [1013-डी, ई-एफ, एच; 1014-बी-सी]

11. धारा की संवैधानिक वैधता को चुनौती

140 (5) कंपनी अधिनियम, 2013 विफल हो जाता है। धारा 140 (5) न तो भेदभावपूर्ण, मनमाना और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) का उल्लंघन है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। विवादित फैसला

और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 140 (5) के तहत आवेदन/कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने के लिए पारित आदेश कि लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसलिए उसके बाद वह बनाए रखने योग्य नहीं है, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने एन. सी. एल. टी. के उस आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बाद भी, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही बनाए रखने योग्य होगी, जिससे भारत संघ और अन्य को रद्द कर दिया जाता है।

डीलोइट हास्की और एलएलपी बेचता है

और अलग रख दें। अधिनियम, 2013 की धारा 1 के तहत आवेदन/कार्यवाही को उसके बाद भी बनाए रखने योग्य माना जाता है।

संबंधित लेखा परीक्षकों और अब एन. सी. एल. टी. का इस्तीफा कानून के अनुसार पूछताछ करने के बाद और उसके बाद ऐसे अंतिम या आगे के परिणामों के आधार पर ऐसे आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करने के लिए जो दूसरे प्रावधान के तहत प्रदान किए गए हैं।

धारा 140 (5) का अनुसरण किया जाएगा। [पैरा 16] [1014-डी-जी]

देवास मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. (2023) 1 एस. सी. सी. 216; एक अधिवक्ता बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (1989) पूरक 2 एस. सी. सी. 25: [1988] 3 पूरक। एससीआर

361 ; आई. सी. ए. आई बनाम एल. के. रत्न और अन्य। (1986) 4 एससीसी 537: [1986] 3 एस. सी. आर. 1049; धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम।

भारत संघ (2019) 5 एससीसी 480: [2019] 6 एससीआर 307;

एस. ई. बी. आई. बनाम सुनील कृष्ण खेतान (2023) 2 एससीसी 643; तोलाराम रेलुमल बनाम। बॉम्बे राज्य [1955] 1 एस. सी. आर. 158; भुवाल्का स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम। यूओआई (2017) 5

एस. सी. सी. 598 [2017] 2 एस. सी. आर. 993; संत लाल गुप्ता बनाम।

मॉडर्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (2010) 13

एस. सी. सी. 336 [2010] 13 एस. सी. आर. 621; बी. हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ए. आई. आर 2018 एस. सी. 2804: [2018] 4 एस. सी. आर. 496; सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ (2003) 3 एस. सी. सी 186: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 222; पासुपुलेती वेंकटेश्वरलु बनाम। मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स (1975) 1 एससीसी 770 [1975] 3 एससीआर

958 ; कैरोना लिमिटेड बनाम पार्वती स्वामीनाथन एंड संस

(2007) 8 एस. सी. सी. 559 [2007] 10 एस. सी. आर. 656; अरुण कुमार बनाम। भारत संघ (2007) 1 एससीसी 732: [2006] 6 पूरक। एससीआर 290; बलराम गर्ग बनाम। एस. ई. बी. आई. (2022) 9 एस. सी. सी. 425; सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी (2019) 5 एस. सी. सी. 266 [2019] 5 एस. सी. आर. 91; मनसुखभाई विठ्ठलदास चौहान बनाम। गुजरात राज्य (1997) 7 एससीसी 622: [1997] 3 पूरक। एससीआर 705; के. के. मिश्रा बनाम। मध्य प्रदेश (2018) 6 एस. सी. सी. 676: [2018] 5 एस. सी. आर. 325;

अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा बनाम। गुजरात राज्य
(1995) 5 एस. सी. सी. 303 [1995] 2 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 637; टी. ताकानो बनाम।
एस. ई. बी. आई (2022) 8 एस. सी. सी. 162 और मो. इकबाल अहमद बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य
(1979) 4 एससीसी 172:

[1979] 2 एस. सी. आर. 1007 संदर्भित है।

पी. एम. सी. मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य 20

एम. डब्ल्यू. एन. (करोड़) 454; कमल लोचन सेन बनाम। की स्थिति

(1982) 54 सीएलटी 509; एवी धर्म रेड्डी बनाम। राज्य

& ओआरएस। 2011 सी. आर. आई. एल. जे 185-संदर्भित।

यूसुफल्ली मुल्ला नूबभाँय बनाम। राजा 1949 क्रि ।
और गोकुलचंद द्वारकादास मोरारका बनाम। द.

(1947- 48) 75 आई. ए. 30 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

(2023) 1 एससीसी 216

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1988] 3 पूरक। एससीआर 361

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[1986] 3 एससीआर 1049

पैरा 4

संदर्भित किया गया है

[2019] 6 एससीआर 307

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2023) 2 एस. सी. सी. 643

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1955] 1 एससीआर 158

	संदर्भित किया गया है	पैरा
[2017] 2 एससीआर 993	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
[2010] 13 एससीआर 621	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
[2018] 4 एससीआर 496	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
[2002] 5 पूरक। एससीआर 222	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
[1975] 3 एससीआर 958	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
[2007] 10 एससीआर 656	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
[2006] 6 पूरक। एससीआर 290	संदर्भित किया गया है	पैरा
	संदर्भित किया गया है	पैरा
(2022) 9 एससीसी 425	संदर्भित किया गया है	पैरा

[2019] 5 एससीआर 91

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1997] 3 पूरक। एससीआर 705

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2018] 5 एस. सी. आर. 325

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1995] 2 पूरक। एससीआर 637

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2022) 8 एससीसी 162

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1979] 2 एससीआर 1007

संदर्भित किया गया है

पैरा यूनियन ऑफ इंडिया एंड एंडर V. डीलोट्ट हैस्कन और एलएलपी बेचता है

आपराधिक/नागरिक अपील न्यायनिर्णय: अपराधी

2022 की अपील Nos.2305-2307। 2019 के सी. आर. एल. डब्ल्यू. पी. Nos.5023,5035 और 5036 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.04.2020 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील Nos.2302-2303, 2022 की सिविल अपील Nos.793, 2022 की आपराधिक अपील No.2298, 2022 की सिविल अपील No.801, 2022 की आपराधिक अपील No.2299, 2022 की सिविल अपील No.877, आपराधिक अपील Nos.2300 और 2022 की 2304 बलबीर सिंह, संजय जैन, ए. एस. जी., बालासुब्रमण्यम, अरविंद दातार, वी. गिरि, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, डेरियस खंबाटा, नीरज किशन

कौल, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, नमन टंडन, समरवीर सिंह, आदित्य सिक्का, कानू अग्रवाल, हिमांशु गुप्ता, विकास कुमार झा, सुश्री रितु आनंद, सुश्री वसुधा विजयशील, अधिराज सिंह चौहान, सुश्री पद्मजा शर्मा, सुश्री नीला केदार गोखले, सुश्री संस्कृति पाठक, सुश्री बानी दीक्षित, अरविंद कुमार शर्मा, रजत नायर, भुवन कपूर, अनुकल्प जैन, दीपवली दत्ता, प्रत्यूष श्रीवास्तव, सुश्री मीशा रोहतगी मोहता, सुश्री सुवेणी भागत, सुश्री आयुषी शर्मा, नकुल मोहता, निश्चया निगम, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, राहुल द्वारकादास, सुश्री प्राची।

धनानी, सुश्री ऋषिका हरीश, सुश्री नियति कोहली, सुश्री जूही बहिरवानी, प्रथम वीर अग्रवाल, सुश्री रोहिणी जैसवाल, सुश्री मानवी अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, वी. पी. सिंह, आदित्य जालान, सुश्री अन्वया घोष, राघव सेठ, सुश्री भाग्य के. यादव, सुश्री वन्या छाबड़ा, अनंत मिश्रा, सुश्री श्रेया चौधरी, ब्रायन मोसेस, सुश्री आकांक्षा कौल, अदित खुराना, सुश्री विधि ठाकुर, प्रस्तुत दलवी, चंद्र प्रकाश, भारत बागला, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सुश्री कीर्ति दधीच, सचिन पाटिल, उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

विचाराधीन याचिकाएँ:

1. आपराधिक अपीलों/दीवानी अपीलों का यह समूह आई. एल. एंड. एफ. एस. वित्तीय सेवा लिमिटेड (इसके बाद 'आई. एफ. आई. एन.' के रूप में संदर्भित) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) (इसके बाद 'अधिनियम, 2013' के रूप में संदर्भित) और दिनांकित 'आई. डी. 1' (इसके बाद 'आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) की व्याख्या से संबंधित कानून के सामान्य प्रश्न (ओं) उठाता है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.1 आपराधिक अपील सं। 2305-2307 / 2022 , आपराधिक अपील सं। 2302-2303 / 2022 और आपराधिक अपील सं. 2300/2022 द्वारा दायर किया गया है।

भारत संघ, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य निर्णय को चुनौती देता है और

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका सं. 1 में पारित आदेश। 4144 & 4145 2019 की और अन्य सहयोगी रिट याचिकाएँ,

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने, हालांकि यह बरकरार रखा कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) असंवैधानिक नहीं है, भारत संघ द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) को जारी किए गए अधिनियम, 2013 की धारा 212 (14) के तहत निर्देश को दरकिनार कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप एस. एफ. आई. ओ. द्वारा आपराधिक शिकायत सं. विशेष अदालत (कंपनी अधिनियम) और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई की फाइल पर सीसी 20/2019, भारत संघ और एसएफआईओ ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

1.2 आपराधिक अपील सं। 2302-2303 / 2022 , यह चुनौती आई. एल. एंड एफ. एस. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षक, अर्थात् बी. एस. आर. एंड एसोसिएट्स एल. एल. पी. (बी. एस. आर.) और आपराधिक अपील संख्या से संबंधित है। 2305-2307 / 2022 और आपराधिक अपील सं. 2300/2022, चुनौती आई. एफ. आई. एन. के एक अन्य लेखा परीक्षक, डेलॉयट हास्किल्स एंड सेल्स एल. एल. पी. (संक्षेप में,

' डेलॉयट) और आई. एफ. आई. एन. के पूर्व निदेशक हरि शंकरन।

1.3 आपराधिक अपील सं। 2298/2022 , 2299/2022 & 2304/2022 डेलॉयट और उसके दो भागीदारों द्वारा आरोपित को चुनौती देते हुए दायर किया गया है

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश जहां तक वह अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की संवैधानिकता को बरकरार रखता है।

1.4 सिविल अपील सं। 793/2022 , 801/2022 & 877/2022 डेलॉयट और उसके दो भागीदारों द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया है

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधिकरण दिनांक 04.03.2020।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

2. संक्षेप में वर्तमान कार्यवाही की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह की कंपनियों द्वारा चूक की एक श्रृंखला, जिनका कुल ऋण बोझ रु. 500 करोड़ से अधिक था। 91,000 करोड़, हुआ

जून से सितंबर, 2018 के बीच और भारत के मुद्रा बाजारों को ध्वस्त करने की धमकी दी, कॉर्पोरेट बांड की पैदावार पर दबाव डाला और शेयर बाजार में बिकवाली की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.09.2018 जारी किया

आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा भारत संघ से अनुरोध करते हुए भारत संघ के निगमित कार्य मंत्रालय से और अन्य बनाम।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम, 2013 के तहत कार्रवाई करना। जापन और टिप्पणी में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि -

(अ)

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह ऋण संक्रमण से जूझ रहा था

लगभग रु. 91,000 आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह में रु. 6950 इक्विटी शेयर पूंजी और भंडार में करोड़

कम से कम 13 बार लाभ उठाना। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 में आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह ने 1,50,000 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया है। 2670 करोड़; यह ऋण संक्रमण, प्रथम दृष्टया, अंतर के कारण था

(ख)

अन्य रूप से आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह में निगमित प्रशासन की विफलता और बंद पड़े खाते; और आगे कोई चूक कुँ के लिए विनाशकारी होगी।

(ग)

वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था का होना।

2.1 समानांतर में, निगमित कार्य मंत्रालय, अधिनियम की धारा 208 के तहत कंपनी पंजीयक से एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर, 2013 , एस. एफ. आई. ओ. को आई. एल. एंड. एफ. एस. और उसकी सहायक कंपनियों के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया।

2.2 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक कंपनी याचिका दायर की

निगमित मामले जो बदले में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा एन. सी. एल. टी. के साथ 31.10.2018 पर दायर किया गया था, द्वारा पारित आदेश के अनुसार 01.10.2018 पर NCLT।

2.3 कार्यालय आदेश दिनांक 30.09.2018 निर्देशन के आगे

एस. एफ. आई. ओ. द्वारा शुरू की जाने वाली जांच और एक ई-मेल दिनांक 01.11.2018, एस. एफ. आई. ओ. ने आई. एल. एंड. एफ. एस. और एक कर्मचारी के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह से संबंधित कल्याण न्यास। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक "अंतरिम रिपोर्ट" मांगी थी, जिसे धारा के अनुसरण में बुलाया गया था।

212 (11) अधिनियम, 2013 का प्रावधान है कि एक अंतरिम रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिपोर्ट अंतरिम निष्कर्ष हैं और अंतरिम रिपोर्ट "उपरोक्त अंतरिम निष्कर्षों के आधार पर" प्रस्तुत करके समाप्त होती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतरिम रिपोर्ट उन व्यक्तियों पर थी जो आईएल एंड एफएस समूह के मामलों के नियंत्रण में थे और उनके द्वारा की गई अवैधताओं और धोखाधड़ी पर थी। 2.4 अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी याचिका संख्या 3638 में एक विविध आवेदन दायर किया।

2018 आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह में कंपनियों के पूर्व निदेशकों के खिलाफ, जो उन्हें उक्त कार्यवाही में शामिल करने और उनकी अचल/चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश देने की मांग कर रहे हैं।

2.5 अंतरिम रिपोर्ट और प्रथम दृष्टया राय के आधार पर

आई. एल. एंड. एफ. एस., आई. एफ. आई. एन. और आई. एल. एंड. एफ. एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आई. टी. एन. एल.) के खातों को फिर से खोलने और पुनर्गठित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 130 के तहत कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिका दायर की। धारा 130 याचिका में पारित दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, एन. सी. एल. टी. ने निर्देश दिया कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों के आई. एल. एंड. एफ. एस., आई. एफ. आई. एन. और आई. टी. एन. एल. के खातों को इस आधार पर फिर से खोला जाए कि आई. एल. एंड. एफ. एस., आई. एफ. आई. एन. और आई. टी. एन. एल. के मामलों को वित्तीय विवरणों/खातों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हुए कुप्रबंधित किया गया था।

2.6 आई. एफ. आई. एन. (बी. एस. आर. एंड. डेलॉयट) के लेखा परीक्षकों को धारा 130 याचिका का नोटिस दिया गया था जिन्होंने उक्त याचिका का विरोध किया था। दिनांकित आदेश

01.01.2019 एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित याचिका को आई. एफ. आई. एन. के पूर्व निदेशकों में से एक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया था। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 31.01.2019 के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने उक्त पूर्व निदेशक द्वारा दायर दीवानी अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार, इस न्यायालय ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने को बरकरार रखा

130 कंपनी अधिनियम, 2018।

2.7 भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने आर. बी. आई. अधिनियम, 1934 की धारा 45 एन के तहत आई. एल. एंड. एफ. एस. और आई. एफ. आई. एन. का निरीक्षण शुरू किया। जाँच/निरीक्षण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने आई. एफ. आई. एन. को एक जाँच/निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.03.2019 प्रस्तुत की। इसके बाद आई. एफ. आई. एन. ने एक

अधिनियम, 2013 की धारा 140 (1) के तहत बी. एस. आर. को अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें लेखा परीक्षकों के रूप में हटाने की मांग करने वाला नोटिस। बी. एस. आर. ने अधिनियम की धारा 140 (1) के तहत आई. एफ. आई. एन. द्वारा दिए गए नोटिस का लिखित जवाब दाखिल किया।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

2013 नोटिस में आरोपों का खंडन करना। आई. एफ. आई. एन. द्वारा 29.05.2019 पर एक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें बी. एस. आर. का भी प्रतिनिधित्व किया गया/उपस्थित किया गया।

2.8 कार्यालय आदेश दिनांक 30.09.2018 के अनुसार, एस. एफ. आई. ओ. ने आई. एल. एंड एफ. एस. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एस. एफ. आई. ओ.) की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट करें।

2.9 निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) और एस. एफ. आई. ओ. से कार्यवाही/अभियोजन शुरू करने का अनुरोध किया। एस. एफ. आई. ओ. को भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 420 और 120 बी के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 447 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही/अभियोजन शुरू करने के लिए कहा गया था। क्षेत्रीय निदेशक को अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत एक याचिका दायर करने के लिए कहा गया था।

2.10 इसके बाद एस. एफ. आई. ओ. ने सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश-कंपनी अधिनियम) के समक्ष 30.05.2019 पर आपराधिक शिकायत दर्ज की।

मुंबई, अन्य के अलावा, आई. एफ. आई. एन. के लेखा परीक्षकों/पूर्व लेखा परीक्षकों के खिलाफ सी. सी. सं. 20/2019 है।

2.11 इसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने आई. एफ. आई. एन. के लेखा परीक्षकों, अर्थात् बी. एस. आर. और डेलॉयट और सगाई भागीदारों के साथ-साथ उनकी टीम के खिलाफ अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) दिनांक आई. डी. 1 के तहत एक याचिका दायर की। धारा के तहत याचिका में

140 (5) , अन्य बातों के साथ-साथ बी. एस. आर. को आई. एफ. आई. एन. के लेखा परीक्षकों के रूप में हटाने का अनुरोध किया गया था; यह घोषणा करें कि डेलॉयट को वित्त वर्ष के लिए आई. एल. एंड एफ. एस. के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में हटाया गया माना जाएगा। 2012-13 से एफ. वाई. 2017-18; निगम कार्य मंत्रालय को अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के पहले प्रावधान के तहत आई. एफ. आई. एन. के लिए एक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की अनुमति दें; और घोषणा/निर्देश दें कि बी. एस. आर., इसके संलग्न भागीदार, डेलॉयट और इसके संलग्न भागीदार अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के दूसरे प्रावधान के तहत पांच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे।

2.12 बी. एस. आर. ने आई. एफ. आई. एन. को दिनांक 19.06.2019 का त्याग पत्र जारी किया और साथ ही इसके अनुसार नियामक फाइलिंग को पूरा किया।

त्यागपत्र दें।

2.13 बी. एस. आर. और उसके भागीदारी भागीदारों ने अन्य बातों के साथ-साथ एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 140 (5) याचिका के लिए दिनांक 19.06.2019 पर एक जवाब दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि (i) वे अब आई. एफ. आई. एन. के लिए लेखा परीक्षक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसलिए धारा 140 (5) नहीं है। उन पर लागू; और (ii) धारा 140 (5) बी. एस. आर. के खिलाफ धोखाधड़ी के किसी भी मामले को प्रदर्शित नहीं करती है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.14 डेलॉयट ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 140 (5) याचिका की रखरखाव को इस आधार पर चुनौती देते हुए दिनांक 19.06.2019 पर एक आवेदन दायर किया कि डेलॉयट अब आई. एफ. आई. एन. के लिए लेखा परीक्षक नहीं है। बी. एस. आर. और उसके जुड़ाव भागीदारों ने भी एक आवेदन दायर कर इसे चुनौती दी। एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 140 (5) याचिका की स्थिरता इस आधार पर कि बी. एस. आर. अब आई. एफ. आई. एन. के लिए लेखा परीक्षक नहीं है।

2.15 धारा 140 (5) याचिका की रखरखाव को चुनौती देने वाले आवेदनों पर लेखा परीक्षकों (बी. एस. आर. और डेलॉयट) को सुनने के बाद, एन. सी. एल. टी. ने धारा 140 (5) याचिका की रखरखाव को बरकरार रखते हुए एक आदेश पारित किया। इसके बाद, बी. एस. आर. ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की शक्तियों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की; जारी किए गए निर्देश और धारा की रखरखाव को बरकरार रखने वाले एन. सी. एल. टी. के आदेश।

140 (5) याचिका।

2.16 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की वैधता को बरकरार रखा है,

अदालत ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की व्याख्या की है और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है जिसमें धारा 140 (5) याचिका की स्थिरता को बरकरार रखा गया है और धारा 140 (5) याचिका को रद्द कर दिया है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को दरकिनार/रद्द कर दिया है।

एस. एफ. आई. ओ. और एस. एफ. आई. ओ. द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द/अलग कर दिया है। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

भारत संघ की ओर से प्रस्तुतियाँ:

3. भारत संघ की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने जोरदार ढंग से कहा है कि विवादित फैसले और आदेश में उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की गलत व्याख्या की है, हालांकि उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की व्याख्या के संबंध में, उच्च न्यायालय ने एक कंपनी में लेखा परीक्षक के परिवर्तन को प्रेरित करने/प्रभावित करने के रूप में विधायी इरादे को समझाया है।

जहाँ धोखाधड़ी का संदेह है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद उच्च न्यायालय ने गलती से यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा के पीछे का इरादा

140 (5) अधिनियम, 2013 का प्रावधान केवल लेखा परीक्षक और कंपनी के बीच मिलीभगत को तोड़ने के लिए है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तदनुसार, उच्च न्यायालय

गलती से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि लेखा परीक्षक और कंपनी के बीच अपवित्र बंधन को हटाया जाता है, या तो हटाया जाता है या त्यागपत्र दिया जाता है, तो अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) अपने उद्देश्य को पूरा करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ और अन्य के अनुसार v.

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायालय, अधिनियम की धारा 140 (5) केवल तभी आकर्षित होती है जब केंद्र सरकार की याचिका के बावजूद, एक लेखा परीक्षक एक बचाव स्थापित करता है और याचिका का तुच्छता से विरोध करता है और इस प्रकार एक अंतिम आदेश आमंत्रित करता है जैसा कि निर्धारित किया गया है। अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत भारत संघ द्वारा दायर याचिका लेखा परीक्षक के बाद के इस्तीफे से संतुष्ट हो गई है और इसलिए भारत संघ द्वारा दायर अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत याचिका अब विचारणीय नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने गलती से धारा 140 (5) याचिका और एन. सी. एल. टी., मुंबई द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़ाया।

3.2 अब जहाँ तक अपराधी को खारिज करने और अलग करने की बात है

कार्यवाहियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थियों ने दो आधारों पर धारा 212 (14) के निर्देश का उल्लंघन किया। सबसे पहले, इस आधार पर कि आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 घंटों के भीतर मुकदमा चलाने का निर्देश जारी करना गैर-विवेक को दर्शाता है। दूसरा, कि आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट एक अधूरी रिपोर्ट थी क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई थी और इसलिए धारा 212 (14) निर्देश अक्षम था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक पहले आधार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने गलती से कहा है कि दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि यह असंभव था कि लगभग 750 पृष्ठों और 32000 पृष्ठों के अनुलग्नकों की रिपोर्ट पर 30 घंटों में विचार किया जा सकता था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि विवेक के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय का यह भी मानना है कि एक वैध मंजूरी का अस्तित्व हो सकता है

एक रिट अदालत में माना जाता है और मुकदमे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

3.3 जहाँ तक आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय संक्षेप में और उसमें गए बिना भी गलती से मानता है कि एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट अधूरी और अभावपूर्ण है और इसलिए धारा 212 (14) निर्देश गलत और/या अमान्य है।

3.4 अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की व्याख्या पर, विद्वान ए. एस. जी., श्री बलबीर सिंह ने हमें विधायी इतिहास और विधायी इतिहास की ओर ले गए हैं।

अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) का आशय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 का शीर्षक "लेखा परीक्षक को हटाना, इस्तीफा देना और विशेष नोटिस देना" है। यह अधिनियम के अध्याय X में दिखाई देता है जिसका शीर्षक "लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक" है। अधिनियम, 2013 की धारा 140 (1) में कंपनी द्वारा लेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 140 (2) और (3) लेखा परीक्षकों [2023] 5 एस. सी. आर. के इस्तीफे से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अधिनियम की धारा 140 (4) सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक के अलावा एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए एक एजीएम में विशेष नोटिस देने से संबंधित है और उस संबंध में प्रक्रिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि किसी कंपनी का लेखा परीक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से कार्य कर रहा है या उसे बढ़ावा दे रहा है या

किसी कंपनी के प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी में मिलीभगत, अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) केंद्र सरकार या किसी भी संबंधित व्यक्ति को सहायता के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 140 (5) एन. सी. एल. टी. को एक लेखा परीक्षक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाती है जिसने उपरोक्त तरीके से काम किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) में दो प्रावधान और दो स्पष्टीकरण भी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए पहले परंतुक के अनुसार

धारा 140 (5), केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक आवेदन पर और यदि न्यायाधिकरण का समाधान हो जाता है कि लेखा परीक्षक के किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो न्यायाधिकरण ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आदेश दें कि उक्त लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा और केंद्र सरकार उसके स्थान पर किसी अन्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अधिनियम की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि एक लेखा परीक्षक, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, जिसके खिलाफ न्यायाधिकरण द्वारा धारा 140 (5) के तहत अंतिम आदेश पारित किया गया है, नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। आदेश पारित होने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी का लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक भी धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान लेखा परीक्षक

आदेश पारित होने की तारीख से पाँच साल की अवधि और यहां तक कि ऐसा लेखा परीक्षक भी कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से त्रुटि हुई कि एक बार लेखा परीक्षक के इस्तीफा देने के बाद अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा और/या आगे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

3.5 इसके बाद, विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह ने हमें लिया और अधिनियम की धारा 140 (5) के विधायी इतिहास का उल्लेख इस प्रकार किया:

अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) का विधायी इतिहास

अगस्त 2004 के आसपास, सरकार ने प्रक्रिया शुरू की कंपनी अधिनियम, 1956 की समीक्षा और एक नए एन ऑफ इंडिया का मसौदा तैयार करना।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

डॉ. जे. जे. ईरानी की अध्यक्षता में कार्य कंपनी कानून के प्रावधानों पर सिफारिशें।

कंपनी विधेयक 2008 और कंपनी विधेयक 2009

आई. जे. जे. ईरानी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंत्रालय ने कंपनी विधेयक, 2008 तैयार किया और पेश किया 23 अक्टूबर, 2008 को लोकसभा के समक्ष भी ऐसा ही हुआ। 2008 के विधेयक को उनकी जांच के लिए वित्त विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (पी. एस. सी.) को भेजा गया था। हालाँकि, पी. एस. सी. द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा को भंग कर दिया गया था और इसलिए 2008 का विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 107 (5) के अनुसार समाप्त हो गया।

ii. तदनुसार, कंपनी विधेयक 2009 में पेश किया गया था

लोकसभा 15 जुलाई, 2009 को या उसके आसपास। 2009 का विधेयक भी पी. एस. सी. को भेजा गया था। 2009 के विधेयक की विशेषताओं की पहचान करते हुए, अगस्त 2010 की पी. एस. सी. रिपोर्ट में मुख्य विशेषताओं को नोट किया गया है कि "लेखा परीक्षकों की भूमिका, अधिकार और कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया है।

यह परिभाषित किया गया है ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके।

iii. 2009 के विधेयक में अंतर्निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए, पी. एस. सी. ने रिपोर्ट में कहा है कि अन्य सिद्धांतों के अलावा, 2009 के विधेयक में अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

" मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता, पारदर्शिता में वृद्धि और

व्यापक प्रकटीकरण आधारित व्यवस्था पर जोर दिया गया; जैसे-जैसे कंपनियां बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं और हितधारकों की संख्या और सीमा के साथ वैश्वीकृत होती हैं, जिससे उचित नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता होती है।
आंतरिक तंत्र /प्रक्रियाओं के माध्यम से स्व-विनियमन, मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर आधारित होगा; केंद्र सरकार तभी कदम उठाएगी जब कुशासन लागू होगा

जगह।

कॉर्पोरेट मिस में हाल के अनुभवों के प्रकाश में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के लिए लेखा परीक्षकों का शासन, लेखा परीक्षा की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

आरा।

अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाए; कठोर संयुक्त और व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित किया जाए; निरीक्षण की स्थापना मानकों को निर्धारित करने और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए निकाय की सिफारिश की गई "

iv. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि पी. एस. सी. द्वारा विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न सुझाव दिए गए थे जो थे - केंद्र सरकार द्वारा निगमित। इन सुझावों को पढ़ने पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता एक प्रमुख बिंदु था।

वी. महत्वपूर्ण रूप से, रिपोर्ट में, पी. एस. सी. ने नोट किया है कि 2009 के विधेयक में 1993 के बैंकिंग और बैंकिंग पर जे. पी. सी. के सुझाव शामिल हैं।

प्रतिभूति बाजार घोटाला और शेयर बाजार घोटाले पर 2002 जे. पी. सी.। इसका मतलब यह है कि 2009 का विधेयक बढ़ती कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट उद्योग के पिछले अनुभवों की भी पराकाष्ठा थी। सुझावों में से एक लेखा परीक्षकों के लिए सख्त जवाबदेही प्रदान करना था। इसके अलावा, उसी पृष्ठ के आधार पर, पी. एस. सी. ने नोट किया कि 2009 के विधेयक ने अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षकों के लिए पर्याप्त नागरिक और आपराधिक दायित्व प्रदान करके वैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिक जवाबदेह बनाने का प्रावधान करके नियामक प्रावधानों और शासन को और अधिक सख्त बना दिया है।

vi. रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लेखा परीक्षकों की भूमिका, जिम्मेदारी, कर्तव्यों और विनियमन और नियामक और प्रवर्तन प्रावधानों पर एक लंबी चर्चा हुई थी।

विशेष रूप से, रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों से संबंधित प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय रूप से, यह सुझाव दिया गया था कि 2009 के विधेयक का खंड 123 (10) (जिसमें धोखाधड़ी का पता चलने पर एन. सी. एल. टी. द्वारा लेखा परीक्षक को हटाने का प्रावधान है) और

अधिनियम की धारा 140 (5) के अनुरूप) को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि एक लेखा परीक्षक को

न्यायाधिकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होना चाहिए। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" 34.समिति को सुझाव प्राप्त हुए हैं कि

लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान करने की आवश्यकता है और

लेखा परीक्षक अधिक सख्त जैसे कि:

भारत और एक और बनाम। डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

(घ) के मामले में उपयुक्त दंड का प्रावधान किया जा सकता है -

इन प्रावधानों का उल्लंघन।

(ई) (i) विधेयक का खंड 123 (10) न्यायाधिकरण को सशक्त बनाता है, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने किसी मामले में कार्य किया है।

कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश देने के लिए धोखाधड़ी के तरीके से या किसी भी धोखाधड़ी में उकसाया/मिलीभगत की गई। सुझाव दिए गए हैं कि इन प्रावधानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेखा परीक्षक द्वारा धोखाधड़ी या उकसाने के कार्य को शामिल करने के लिए स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि विधेयक में यह प्रावधान किया जा सकता है कि यदि लेखा परीक्षक, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, जिसके खिलाफ इस खंड के तहत न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है, वह लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होना चाहिए। पाँच वर्ष की अवधि के लिए किसी भी कंपनी का।

ई-कंपनी विधेयक, 2011

स्थायी समिति और विभिन्न हितधारकों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक पेश करने के लिए 2009 के विधेयक को वापस ले लिया।

स्थायी की सिफारिशों को शामिल करना समिति और विभिन्न हितधारक। नतीजतन, 2011 का विधेयक दिसंबर, 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार और शामिल किया गया था

कंपनी विधेयक, 2009 के संबंध में पिछली स्थायी समिति द्वारा बनाया गया। इस पहलू को दर्ज किया गया है

कंपनी विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण,

2011 . इस मोड़ पर, यह बीच में सहन करना महत्वपूर्ण है कि

2009 के विधेयक के खंड 123 (10) के लिए स्थायी समिति का सुझाव (जिसमें लेखा परीक्षक को हटाने का प्रावधान है)

एन. सी. एल. टी. ने यह पता लगाने पर कि धोखाधड़ी हुई है):

प्रावधान को और अधिक कठोर बनाएँ; और

एक लेखापरीक्षक के लिए परिणामों का प्रावधान करना जब ऐसा हो लेखा परीक्षक को धोखाधड़ी करते हुए पाया गया है और वह है

इस तरह की धोखाधड़ी के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा हटा दिया गया।

2001 का विधेयक संबंधित प्रावधानों को समेकित करता है -

2011 के विधेयक के खंड 140 नामक एक खंड में लेखा परीक्षकों को हटाना। इसके अलावा, 2011 के विधेयक (2009 के विधेयक की तरह) में 5 एस. सी. आर. को बरकरार रखा गया है।

जेपीआईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह पता चलने पर कि लेखा परीक्षक को हटाने की एन. सी. एल. टी. की शक्ति

लेखा परीक्षक ने 2011 के विधेयक के खंड 140 (5) में धोखाधड़ी की है। सबसे विशेष रूप से, रिपोर्ट में निहित स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल करने वाला 2011 का विधेयक, एक ऐसे लेखा परीक्षक के लिए परिणाम प्रदान करता है जिसने एन. सी. एल. टी. द्वारा धोखाधड़ी की है और जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी के लिए हटा दिया गया है। यह विधेयक के खंड 140 (5) (विशेष रूप से दूसरा परंतुक) के परंतुक के माध्यम से किया गया है। 2011 के विधेयक की धारा 140 (5) का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

" (5) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायाधिकरण या तो स्वतः संज्ञान लेता है या केंद्र सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा उसे किए गए आवेदन पर। संबंधित , यदि यह संतुष्ट है कि किसी कंपनी का लेखा परीक्षक

उसने, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी के तरीके से काम किया हो या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की हो। आदेश द्वारा कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश दे सकता है:

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार द्वारा आवेदन किया जाता है और न्यायाधिकरण का समाधान हो जाता है कि लेखा परीक्षक के किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर एक आदेश देगा कि वह लेखा परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा और केंद्र सरकार उसके स्थान पर दूसरे लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है:

बशर्ते कि एक लेखा परीक्षक, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है, पात्र नहीं होगा

आदेश पारित होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और लेखा परीक्षक भी धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए शब्द

" लेखा परीक्षक में "लेखा परीक्षकों की एक फर्म शामिल होती है"।

इसके बाद, जनवरी 2012 में, 2011 के विधेयक को लोकसभा द्वारा स्थायी समिति के समक्ष रखा गया। स्थायी समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसे अंतिम रूप दिया है, और जहां तक भारत संघ और अन्य के दंड और मार्गदर्शक सिद्धांतों का संबंध है।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

खंड 140 (5) का संबंध है, आगे कोई मार्गदर्शन नहीं है।

उसी के पीछे विधायी इरादे पर।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2011 के खंड 140 (5) का परीक्षण

वी.

विधेयक अपरिवर्तित रहा है, इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की वर्तमान धारा 140 (5) के रूप में अधिनियमित किया गया है।

अधिनियम की धारा 143 (12) के अनुसार और अधिनियम की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के रूप में शामिल एक ऐसे लेखा परीक्षक को बनाने का प्रावधान है जो धोखाधड़ी से काम कर रहा है या 5 साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी में लेखा परीक्षक होने से मिलीभगत कर रहा है। यह है। प्रस्तुत किया कि इसलिए, अधिनियम की धारा 140 (5) के पीछे की सार्वजनिक नीति बहुत स्पष्ट है-एक लेखा परीक्षक को 5 साल की अवधि के लिए कोई भी वैधानिक लेखा परीक्षा करने से रोकने के लिए जो एक कंपनी में धोखाधड़ी या मिलीभगत करने के लिए पाया गया है। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट के मामले में रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। लिमिटेड वी. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. ने (2023) 1 एस. सी. सी. 216 में रिपोर्ट किया।

3.7 विद्वान ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 140 (5) अधिनियम के अध्याय X में दिखाई देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अध्याय X विशेष रूप से 'लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों' से संबंधित है। की धारा 143

यह अधिनियम लेखा परीक्षकों की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 143 की उप-धारा (12) में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि यदि लेखा परीक्षकों के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धोखाधड़ी का अपराध किया जा रहा है या किया गया है

कंपनी में प्रतिबद्ध, लेखा परीक्षक केंद्र सरकार को मामले की रिपोर्ट करेगा। इस संबंध में जारी नियमों के तहत विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है।

3.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 144 प्रदान करती है

कि लेखा परीक्षक कुछ सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है और वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक "प्रबंधन सेवाएं" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्य यह है कि लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा सेवाओं के दायरे से बाहर इसकी किसी भी गतिविधि से अप्रभावित एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। लेखा परीक्षक को कंपनी को कोई भी प्रबंधन सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 144 के तहत बनाया गया निषेध और प्रतिबंध मुख्य रूप से कंपनी और अन्य हितधारकों जैसे ऋणदाताओं और निवेशकों और बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा के लिए है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन प्रावधानों और अंतर्निहित सार्वजनिक नीति को पृष्ठभूमि में रखते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) पर विचार किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के सादे शब्दों में एन. सी. एल. टी. के लिए, या तो स्वतः या केंद्र सरकार/किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी लेखा परीक्षक के आचरण या धोखाधड़ी में उसकी संलिप्तता की जांच/जांच करने और लेखा परीक्षक के धोखाधड़ीपूर्ण आचरण के संबंध में संतुष्टि प्राप्त करने का प्रावधान है। यह प्रावधान आगे यह निर्धारित करता है कि माननीय एन. सी. एल. टी. की संतुष्टि के परिणामस्वरूप अंततः एक लेखा परीक्षक का परिवर्तन हो सकता है।

3.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 140 (5) के पहले परंतुक को एक अंतरिम या अस्थायी उपाय के रूप में माना जाता है ताकि

वर्तमान लेखा परीक्षक को जारी रखने और उसे केंद्र सरकार द्वारा नामित एक लेखा परीक्षक के साथ प्रतिस्थापित करने से रोक दिया गया है जो प्रथम दृष्टया इस संतुष्टि के आधार पर है कि धोखाधड़ी की गई है और जब परिस्थितियाँ प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती हैं। यह एक अंतरिम आदेश है और एक अस्थायी आदेश के समान काम करता है।

निलंबन।

3.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक जो एक मूल प्रावधान की प्रकृति में है, एक पर सक्रिय होता है एक लेखा परीक्षक द्वारा धोखाधड़ी या मिलीजुली आचरण के बारे में माननीय एन. सी. एल. टी. की संतुष्टि को दर्ज करने वाला आदेश और उसके परिणामस्वरूप उसे कंपनी से हटा दिया जाता है और उसे 5 साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी में लेखा परीक्षक होने से रोकता है। पहले परंतुक के तहत एक आदेश अधिनियम की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत अनुध्यात आदेश नहीं है। इस प्रकार, यदि एन. सी. एल. टी. को अंततः यह मानने का कोई आधार नहीं मिलता है कि धोखाधड़ी में धोखाधड़ी या मिलीभगत हुई है, तो ऑडिटर जो अस्थायी रूप से हो सकता है

पहले परंतुक के तहत निलंबित आदेश को फिर से लागू किया जा सकता है।

3.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिनियम की धारा 140 (5) माननीय एन. सी. एल. टी. को आचरण पर निर्णय लेने या जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। किसी लेखा परीक्षक का लेखा परीक्षण करना और यह निर्धारित करना कि क्या लेखा परीक्षक ने धोखाधड़ी के तरीके से खुद को संचालित किया है। यह प्रावधान के संचालन भाग से स्पष्ट है जो धारा के तहत आवश्यक जांच की प्रकृति को अनिवार्य करता है। यह "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी के तरीके से कार्य किया जाता है या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी भी धोखाधड़ी में उकसाया या मिली-जुली है।"

3.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, किसी भी अंतिम आदेश में निश्चित रूप से "धोखाधड़ी" का सकारात्मक या नकारात्मक निर्धारण होगा या "कपटपूर्ण आचरण"। अधिनियम की धारा 140

(5) के तहत धोखाधड़ी का पता लगाने के परिणामस्वरूप, प्रावधान यह दर्शाता है कि धोखाधड़ी/धोखाधड़ी आचरण के निष्कर्ष से लेखा परीक्षक को बदलने का निर्देश देने वाला आदेश "हो सकता है"।

भारत संघ और एक अन्य V. डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

दूसरे परंतुक में आगे स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक लेखा परीक्षक "जिसके खिलाफ अंतिम आदेश पारित किया गया है" वह 5 साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने का पात्र है। उल्लेखनीय रूप से, में उपयोग किए गए शब्द

अधिनियम की धारा 140 (5) का दूसरा प्रावधान "अंतिम आदेश" है न कि "लेखा परीक्षक को इस तरह से हटा दिया गया" या "परिवर्तित लेखा परीक्षक"।

3.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आवश्यकता या आवश्यकता

कंपनी में लेखा परीक्षक का परिवर्तन अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत एन. सी. एल. टी. की शक्ति को सक्रिय/नियंत्रित नहीं करता है। इसके बजाय, यह एक लेखा परीक्षक द्वारा धोखाधड़ी के कार्य की जांच है जो अपनी वैधानिकता का त्याग करता है। निर्धारित स्वतंत्र भूमिका और जिम्मेदारियाँ और प्रबंधन के साथ मिलीभगत या अन्यथा धोखाधड़ी को अंजाम देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रावधान/धारा का सार लेखा परीक्षक के धोखाधड़ीपूर्ण आचरण का निर्धारण है। अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) द्वारा पर्यालोचित परिणामी "निष्कासन" केवल एक कंपनी या संबंधित कंपनी में लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के रूप में नहीं है, बल्कि किसी भी कंपनी से पांच साल की अवधि के लिए है।

3.15 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारा की व्याख्या

140 (5) उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में बनाए गए अधिनियम, 2013 के अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है

अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) और इस प्रकार, उक्त प्रावधान के विपरीत है।

3.16 श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि बहस के दौरान, उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियां दी गईं

ये निम्नानुसार हैं:

क) अधिनियम की धारा 140 (5), अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आलोक में, केवल एक अवज्ञाकारी लेखा परीक्षक को इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

इसलिए, यदि कोई लेखा परीक्षक याचिका दायर करने के बाद इस्तीफा दे देता है

अधिनियम की धारा 140 (5) लेकिन माननीय एन. सी. एल. टी. के समक्ष

उस याचिका पर एक आदेश का उच्चारण करता है, धारा के पीछे का उद्देश्य

140 (5) अधिनियम पूरा हो गया है। अधिनियम की धारा 140 (5) की यह व्याख्या, प्रत्यर्थी के मामले के अनुसार, प्रावधान के सादे शब्दों से स्पष्ट है; ख) धारा 140 (5) के तहत लेखा परीक्षक के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना।

उनके इस्तीफे के बावजूद अधिनियम की धारा 140 (5) को एक परंतुक में पढ़ा जाएगा जो धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही की परिणति तक उनके बने रहने को मानता है।

[2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग) अधिनियम की धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक मनमाना, कठोर और बोझिल है और इसे पढ़ा जाना चाहिए। 5 साल की अवधि के लिए लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने की अनिवार्य अयोग्यता को प्रावधान करने के लिए 5 साल तक की अवधि के लिए पढ़ा जाना चाहिए।

संवैधानिक।

अधिनियम की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत केवल संबंधित लेखापरीक्षा भागीदारों तक ही विस्तार किया जा सकता है, न कि पूरी फर्म और अन्य लेखापरीक्षा भागीदारों तक जो इस अधिनियम से जुड़े नहीं थे। कपटपूर्ण कार्य या कार्य।

3.17 उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ बैठक, यह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

::

क) प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि -

एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता को केवल एक पक्ष के कार्य द्वारा दूर किया जा सकता है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इसका मतलब यह होगा कि धोखाधड़ी के आचरण की जांच बाधित हो सकती है और/या खड़ी हो सकती है।

केवल एक पक्ष के कार्य से संतुष्ट।

ग) अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में (अधिनियम के अनुसार) पूरे निर्माण को अधिनियम की धारा 140 (5) के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उपरोक्त अनुच्छेद 9.17 (ए) और (बी) प्रावधान को एक मृत पत्र में बदलने के लिए है [एन. ई. पी. सी. माइकॉन लिमिटेड बनाम देखें। मैग्मा लीजिंग लिमिटेड

(1999) 4 एससीसी 253]। इसके अलावा, यदि प्रत्यर्थी की व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है, तो यह विभिन्न बेतुकी बातों को जन्म देगी। विशेष रूप से, अन्य कारणों के अलावा:

आई. यह देखते हुए कि यह स्वीकार किया जाता है कि पहला परंतुक एक लेखा परीक्षक के अस्थायी निलंबन या हटाने का प्रावधान करता है, यदि पहले परंतुक के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है और त्रुटिपूर्ण लेखा परीक्षक को प्रतिस्थापित किया जाता है (हालांकि अस्थायी रूप से), तो एक आदेश दूसरा परंतुक कभी भी पालन नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम आदेश की तारीख तक गलती करने वाले लेखा परीक्षक को किसी कंपनी का लेखा परीक्षक नहीं कहा जा सकता है। पहला परंतुक आदेश।

भारत का एन और एक और वी। डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

ii. अधिनियम की धारा 140 (5) के आतंक में काम करने या एक अवज्ञाकारी लेखा परीक्षक को इस्तीफा देने के लिए प्रेरित करने का कोई कारण नहीं है। यह

ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम की धारा 140 (5) का पहला परंतुक संचालित होता है।

लेखा परीक्षक को तुरंत बदलने/हटाने के लिए

केंद्र द्वारा याचिका दायर करने के बाद मौजूदा लेखा परीक्षक

अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत सरकार। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार पहला परंतुक निरर्थक हो जाएगा यदि अधिनियम की धारा 140 (5) के पीछे का इरादा किसी लेखा परीक्षक को इसके लिए प्रेरित करना है।

त्यागपत्र देना।

किसी भी कंपनी के लिए लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने की अयोग्यता

5 साल की अवधि को "पांच साल तक की अवधि" के लिए नहीं पड़ा जा सकता है। यह तब से है:

आई. भविष्य में प्रावधान की आशंका या दुरुपयोग प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए आधार नहीं हो सकता है। [देखें।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया 2021 एससीसी ऑनलाइन

एससी 463 (पैरा 101-102)]

ii. धोखाधड़ी सब कुछ खराब कर देती है और कानून में सजा के आदेश को लंबाई और चौड़ाई की जांच करके बदला नहीं जा सकता है।

धोखाधड़ी से। iii. अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत कार्य करने की अयोग्यता केवल किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए है। यह संबंधित लेखा परीक्षक को आम तौर पर चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में काम करने से नहीं रोकता है। संबंधित व्यक्ति या फर्म कंपनी के खातों से संबंधित कोई अन्य गतिविधि (जो अन्यथा धारा 144 के आधार पर एक लेखा परीक्षक के लिए वर्जित है) जैसे खाता और बहीखाता सेवा, बीमाकृत सेवा आदि या अन्यथा कर सकते हैं। वास्तव में, वर्तमान मामले में, शामिल लेखापरीक्षा फर्मों का लेखापरीक्षा के बाहर उनके व्यवसाय का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है

कार्य. 5 साल का निषेध एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या सेवा के किसी अन्य क्षेत्र के रूप में उनके अभ्यास को प्रभावित नहीं करता है; और iv. 5 साल की निश्चित निषेध अवधि केवल माननीय एन. सी. एल. टी. द्वारा धोखाधड़ी का पता चलने की स्थिति में सक्रिय होती है -

वैधानिक योजना और सार्वजनिक नीति। का सिद्धांत

आनुपातिकता को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां धोखाधड़ी की सीमा की जांच की जानी चाहिए। इस प्रावधान का बहुत ही निवारक प्रभाव कम हो जाएगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अदालत की रिपोर्टों पर हावी होगा

आरा।

अन्य के संबंध में धोखाधड़ी को कायम रखने के लिए राशि

कंपनियाँ।

धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित फर्म और व्यक्तियों के लिए अधिनियम, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन दर्शाता है कि विधायिका

अधिनियम की धारा 140 (5) के परिणाम से संबंधित प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया। अधिनियम की धारा 140 (5) के दूसरे प्रावधान की जांच से पता चलता है कि माननीय एन. सी. एल. टी.

धोखाधड़ी के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष देने की आवश्यकता है और चाहे लेखा परीक्षक एक फर्म हो या एक व्यक्ति। ऐसी कोई धारणा नहीं हो सकती है कि केवल धोखाधड़ी का पता लगाने के संबंध में

एक व्यक्ति स्वचालित रूप से फर्म द्वारा धोखाधड़ी का निर्धारण करेगा। यह धारा 147 के तहत भी प्रदान किया गया है।

अधिनियम जो इस प्रकार है:

(5) जहाँ, किसी कंपनी के लेखापरीक्षा के मामले में एक लेखापरीक्षा फर्म द्वारा संचालित, यह साबित होता है कि लेखापरीक्षा फर्म के भागीदार या भागीदारों ने एक में कार्य किया है या किया है

कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में या उनके द्वारा किसी धोखाधड़ी में धोखाधड़ी या उकसाया गया या मिली-जुली मिली-जुली मिली-जुली देनदारी, चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक, जैसा कि इस अधिनियम में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में प्रावधान किया गया है, ऐसे कार्य के लिए लेखा परीक्षा फर्म और फर्म के संबंधित भागीदार या भागीदारों की होगी।

संयुक्त रूप से और अलग-अलग।

बशर्ते कि किसी लेखापरीक्षा फर्म के आपराधिक दायित्व के मामले में, जुर्माने के अलावा अन्य दायित्व के संबंध में, संबंधित भागीदार या भागीदार, जिन्होंने धोखाधड़ी के तरीके से काम किया या किसी धोखाधड़ी में सहयोग किया या, जैसा भी मामला हो, मिलीभगत की।

केवल उत्तरदायी होगा।

यदि एक लेखा परीक्षक इस्तीफा दे देता है, तो अधिनियम की धारा 140 (5) के प्रावधानों को लागू करना आसान हो जाता है। इसके बजाय, संबंधित लेखा परीक्षक को अधिनियम की धारा 241 (3) और निम्नलिखित के अनुसार कार्यवाही के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है -241 (3) अधिनियम के परिणामस्वरूप एक ही परिणाम प्राप्त होगा और लेखा परीक्षक को किसी भी क्षेत्र में नियुक्त किए जाने के लिए 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा।

किसी के भी आचरण और प्रबंधन से संबंधित कार्य

. यह प्रस्तुत किया जाता है कि:

[भारत का आयन और एक अन्य बनाम। डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

ए। धारा 241 (3) और इसके परिणामी प्रावधान पेश किए गए थे।

14.8.2019 से प्रभावी, जिसने केंद्रीय को अधिकृत किया

सरकार यह घोषित करने के अनुरोध के साथ न्यायाधिकरण में आवेदन करेगी कि अधिनियम की धारा 241 (3) में उल्लिखित व्यक्ति उपयुक्त नहीं हैं

और निदेशक या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए उचित व्यक्ति

किसी भी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से जुड़ा कार्यालय।

बी। "किसी भी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य कार्यालय" का निर्माण, इस पर विचार करना आवश्यक होगा।

धारा के साथ अधिनियमित किए गए परिणामी प्रावधान 241 (3) अधिनियम से। विशेष रूप से, धारा 243 (1 ए) और धारा 243 (2)

अधिनियम से।

(1 ए) वह व्यक्ति जो धारा 242 की उप-धारा (4 ए) के अनुसार एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है, वह निदेशक का पद या आचरण से जुड़े किसी अन्य पद पर नहीं रहेगा।

और उक्त निर्णय की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के मामलों का प्रबंधन (2) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करता है

या उल्लंघन में किसी कंपनी के अन्य निदेशक या प्रबंधक

उप-धारा (1) या उप-धारा (1 क) के खंड (ख) का, और

कंपनी का हर दूसरा निदेशक जो जानबूझकर एक है

इस तरह के उल्लंघन के लिए पक्षकार, जुर्माने से दंडनीय होगा

जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

स्पष्ट रूप से, परिणामी प्रावधान के शब्दों से, यह स्पष्ट है

कि अधिनियम की धारा 241 (3) में विशेष रूप से

" आचरण और प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य कार्यालय "किसी कंपनी के" से वे अभिप्रेत हैं जो प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक जैसे कि प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के समान हैं, न कि

लेखा परीक्षक। सी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 241 (3) में विशेष रूप से उपयोग किए गए शब्द "कंपनी का आचरण और प्रबंधन" हैं। अधिनियम के अनुसार लेखा परीक्षक खातों का एक स्वतंत्र परीक्षक होता है और

आचरण में एक पद धारण करने के लिए नहीं कहा जा सकता है और
कंपनी का प्रबंधन। यह बहुत के खिलाफ विद्रोह होगा

कंपनी अधिनियम, 2013 का फाइबर।

3.19 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि, (i) अधिनियम, 2013 की धारा एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण को सक्षम बनाने के लिए काम करती है जो लेखा परीक्षकों की भूमिका की जांच करने और [2023] 5 एस. सी. आर. पर निर्णय लेने के लिए एक दीवानी न्यायालय की शक्तियों से लैस है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखाधड़ी का ठोस निर्धारण ताकि किसी लेखा परीक्षक को कंपनी से और किसी भी कंपनी से अलग किया जा सके या हटाया जा सके जिसका वह लेखा परीक्षण कर रहा है। यदि यह केवल एक अवज्ञाकारी लेखा परीक्षक के परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक प्रावधान माना जाता है, तो एनसीएलटी को एक लेखा परीक्षक के धोखाधड़ीपूर्ण आचरण की जांच करने की शक्ति प्रदान करने वाले शब्दों को अर्थहीन बना दिया जाएगा; (iii) अधिनियम की धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक अनिवार्य रूप से उपचारात्मक और निवारक है, हालांकि इसका संयोग से दंडात्मक प्रभाव भी हो सकता है। धारा के दूसरे परंतुक का सार्वजनिक उद्देश्य/उद्देश्य स्पष्ट रूप से कंपनियों को पूर्वाग्रह से प्रभावित होने से बचाना है, ऐसे लेखा परीक्षक को, जिसे धोखाधड़ी से काम करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने से रोकना है। 3.20 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह ध्यान रखना उचित है कि:

क) डेलॉयट 2008 से 2008 तक आई. एफ. आई. एन. का सांविधिक लेखा परीक्षक था।

2018. डेलॉयट 2018 में समय के प्रवाह से सेवानिवृत्त हुआ;

बी) बी. एस. आर. को 2017 में संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था;

ग) डेलॉयट और बी. एस. आर. दोनों ने संयुक्त रूप से वैधानिक लेखा परीक्षा का संचालन किया।

वित्तीय वर्ष के लिए आई. एफ. आई. एन. 2017-2018;

ङ) यह याचिका एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि दोनों लेखा परीक्षकों यानी डेलॉयट और बी. एस. आर. ने धोखाधड़ी से काम लिया। इसमें वह अवधि शामिल है जब डेलॉयट एकमात्र लेखा परीक्षक था और उस वर्ष के लिए जब लेखा परीक्षा संयुक्त रूप से की गई थी। बीएसआर द्वारा;

च) याचिका दायर किए जाने के बाद, बी. एस. आर. ने अपना इस्तीफा दे दिया और जुलाई 2019 में या उसके आसपास धारा के तहत भारत संघ की याचिका की स्थिरता को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया।

140 (5) अधिनियम से। डेलॉयट, जो 2018 में सेवानिवृत्त हुई थी, ने भी दायर किया

रखरखाव अनुप्रयोग; और

छ) माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद, भारत संघ ने भारत के प्रथम संघ और अन्य के तहत माननीय एन. सी. एल. टी. की शक्तियों का उपयोग किया।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम की धारा 140 (5) के प्रावधान और एक लेखा परीक्षक था

आई. एफ. आई. एन. के लिए नियुक्त।

3.21 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और ऊपर वर्णित अधिनियम की धारा 140 (5) की सही व्याख्या पर, उच्च न्यायालय ने गलती से

भारत संघ की याचिका की स्थिरता को बरकरार रखते हुए एन. सी. एल. टी. का आदेश अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत और लेखा परीक्षकों के खिलाफ अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही-बीएसआर।

3.22 ऊपर प्रस्तुत अधिनियम की धारा 140 (5) की व्याख्या को देखते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि दाखिल करने के बाद बी. एस. आर. के इस्तीफे का कार्य

अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत याचिका को अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही को शून्य नहीं माना जा सकता है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की व्याख्या किसी भी कार्यवाही को प्रस्तुत करेगी।

चाहे कंपनी के प्रबंधन और/या उसके लेखा परीक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए पूरी तरह से एक पक्ष के डिजाइन के केवल रणनीति से निराश हो। इन परिस्थितियों में, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए। 3.23 जहां तक डेलॉयट का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने याचिका की रखरखाव क्षमता को बरकरार रखा है।

अधिनियम की धारा 140 (5)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 140 (5) में माननीय एन. सी. एल. टी. को यह संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि कंपनी के लेखा परीक्षक ने, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, धोखाधड़ी के तरीके से काम किया या किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की। इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, दोनों लेखा परीक्षकों यानी डेलॉयट और बी. एस. आर. की भूमिका की जांच करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब दोनों वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे थे। व्याख्या को ध्यान में रखते हुए

ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार, न्यायाधिकरण की संतुष्टि के परिणामस्वरूप अंततः लेखा परीक्षक का परिवर्तन हो सकता है अर्थात् बी. एस. आर. का परिवर्तन; हालाँकि, यह अधिनियम की धारा 140 (5) के संदर्भ में माननीय एन. सी. एल. टी. को धोखाधड़ी की जांच करने के लिए दी गई शक्तियों को भी नहीं छीनता है और यदि पाया जाता है तो अपने अंतिम आदेश में डेलॉयट के खिलाफ धोखाधड़ी की संतुष्टि दर्ज करता है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों में, अंतिम आदेश और इसलिए दूसरा परंतुक डेलॉयट और बी. एस. आर. के खिलाफ काम कर सकता है।

एस. एफ. आई. ओ. और आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट द्वारा दायर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवादित आदेश में 5 एस. सी. आर. (2023) को दरकिनार/रद्द कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्देश और आपराधिक शिकायत और एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट

इसे हटा दें:

ए। एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट एक अधूरी जांच पर एक अधूरी रिपोर्ट/रिपोर्ट है और इसलिए 212 (14) निर्देश नहीं दिया जा सका। इस निष्कर्ष का कथित आधार है: (i) एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट में एक एकल अनुच्छेद; और (ii) 212 (14)

निर्देश जो कुछ पहलुओं पर आगे की रिपोर्ट की मांग करता है

स्वयं यह दर्शाता है कि जाँच अधूरी है; और

बी। केंद्र सरकार के समक्ष एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट रखने के 30 घंटे के भीतर 212 (14) निर्देश दिए गए थे।

केंद्र सरकार के लिए आवेदन करना असंभव था

इतने कम समय में अपना दिमाग।

प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित आदेश गलत है क्योंकि:

एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट आई. एफ. आई. एन. की जांच को पूरा करने पर एस. एफ. आई. ओ. द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। कंपनियों में से एक

इसकी जांच की जा रही है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नहीं किया है

इस स्थिति को सुनिश्चित किया कि:

आई. 30 सितंबर, 2018 के एक आदेश द्वारा, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा आई. एल. एंड एफ. एस. और इसके बारे में जांच करने का निर्देश दिया गया था।

सहायक (आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह) जो कुल मिलाकर लगभग 100

169 इकाइयाँ;

ii. आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह के कार्यों का संचालन जो 30 नवंबर, 2018 की एस. एफ. आई. ओ. की अंतरिम रिपोर्ट में निर्धारित किया गया था, स्पष्ट रूप से बताता है कि समूह के भीतर कई परस्पर संबंध थे, लेन-देन आदि थे।

iii. आई. एफ. आई. एन. आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की सहायक कंपनियों में से एक है और

वित्तीय सेवा शाखा। इसने विभिन्न लोगों के लिए उधार लेने में सुविधा प्रदान की।

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह में तृतीय पक्ष से समूह कंपनियाँ

उधारकर्ता और कभी-कभी एक समूह कंपनी से वित्त पोषण दूसरे के लिए;

iv. आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह में विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर संबंधों और ओवरलैप की प्रकृति को देखते हुए, एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट में कहा गया है कि एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट है -

आई. एफ. आई. एन. और आई. एफ. आई. एन. की जांच पूरी होने पर एक रिपोर्ट है;

और [भारत का आयन और एक और बनाम। डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

बी. अंत में, एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की जटिल संरचना और संस्थाओं के बीच परस्पर संबंधों आदि के आलोक में यह बताती है कि यदि आई. एल. एंड एफ. एस. की अन्य समूह कंपनियों की जांच के दौरान आई. एफ. आई. एन. के तहत कोई और उदाहरण या लेनदेन सामने आता है तो एक और रिपोर्ट दायर की जाएगी।

इसका मतलब यह नहीं है कि आई. एफ. आई. एन. की जांच अधूरी है। वास्तव में, कुछ पहलुओं (जो तीसरे पक्ष से संबंधित हो सकते हैं) पर आगे की रिपोर्ट मांगने का निर्देश भी विचलित नहीं करता है

इस स्थिति से कि जाँच अन्य सभी मामलों में पूर्ण है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय प्रस्तुत करने के उद्देश्य की सराहना करने में विफल रहा है और यह मानते हुए मौलिक रूप से गलती की है कि एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट अधूरी है और/या आई. एफ. आई. एन. की जांच अधूरी है। इस मामले में एस. एफ. आई. ओ. द्वारा विस्तृत और व्यापक चर्चा के बाद एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

आई. एफ. आई. एन. और इसमें शामिल कई पक्षों की जांच। यह है।

प्रस्तुत किया कि प्रत्येक लेखा परीक्षक/सीए के खिलाफ कई उल्लंघनों, वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के आचरण की ओर इशारा करते हुए निर्णायक निष्कर्ष थे

संबंधित समय पर लेखा परीक्षक।

बी। बंबई उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के सतह स्तर के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है कि 212 (14) निर्देश 30 घंटे के भीतर जारी किया गया था जो दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है। निम्नलिखित पर विचार किए बिना:

212 (14) दिशा तक जाने वाली प्रक्रिया को संसाधित करना और निर्धारित करना। जहां तक प्रत्यर्थी के जमीनी स्तर के आरोप का संबंध है, भारत संघ ने एक स्पष्ट, पारदर्शी और ठोस व्यवस्था प्रदान की है

या; [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

iii. उत्तरदाताओं के तर्क स्व-सेवारत थे और

विरोधाभासी। विशेष रूप से, यह तर्क कि भारत संघ ने 212 (14) निर्देश जारी करने के लिए लिए गए 30 घंटों की अवधि को देखते हुए अपने दिमाग को लागू नहीं किया, इस तर्क के सीधे विपरीत है कि आगे की रिपोर्ट मांगने का निर्देश (212 (14) निर्देश में निहित) दर्शाता है कि जांच अधूरी है। इस तथ्य के बावजूद कि आई. एफ. आई. एन. की जांच पूरी हो चुकी है, कुछ पहलुओं पर आगे की रिपोर्ट के लिए निर्देश केवल

दिमाग के आवेदन के बाद जारी किए गए हैं।

iv. कानूनी और तथ्यात्मक दुर्भावना की सीमा बहुत अधिक है जिसे गति के सतह स्तर के विवाद से पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रसंस्करण।

वी. लिखित अधिकारिता वाले माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप का दायरा यह निर्धारित करना होगा कि क्या पर्याप्तता थी

निर्देश देने वाले प्राधिकारी के समक्ष सामग्री। वर्तमान मामले में, एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट मुकदमा चलाने का निर्देश देने वाले प्राधिकरण के समक्ष थी-यह तथ्य विवादित नहीं है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रासंगिक सामग्री थी

संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होना।

3.25 अब जहाँ तक उत्तरदाताओं की ओर से यह निवेदन है कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट को दूसरा कहा गया था।

अंतरिम रिपोर्ट और इसलिए एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट होने के कारण, 212 (14) निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि अधिनियम में ऐसा नहीं है।

एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम की धारा 212 (14) के तहत एक निर्देश जारी करने पर विचार करते हुए, श्री बलबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ए. एस. जी. को पता चला है कि अधिनियम, 2013 की धारा 212 (11) के अनुसार, जांच के दौरान, केंद्र सरकार को अंतरिम रिपोर्ट मांगने का अधिकार दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. एफ. आई. ओ. को केंद्र सरकार से अंतरिम रिपोर्ट के अनुरोध के बिना अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने दिनांकित 03.11.2018 पत्र के माध्यम से विशेष रूप से SFIO को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार, एस. एफ. आई. ओ. ने 30.11.2018 दिनांकित एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतरिम रिपोर्ट, एक खाली अवलोकन पर, दर्ज करती है कि यह एक अंतरिम रिपोर्ट है, केंद्र सरकार के अनुरोध को दर्ज करती है अंतरिम रिपोर्ट और इसके निष्कर्षों को अंतरिम निष्कर्षों के रूप में वर्गीकृत करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट से पूरी तरह से अलग है जो

अधिनियम की धारा 212 (12) के तहत खुद को एक जांच रिपोर्ट के रूप में वर्गीकृत करता है, की गई विस्तृत और व्यापक जांच और भारत का संघ और अन्य V.

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

वर्तमान मामले में प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ निर्णायक निष्कर्ष दर्ज करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अंतरिम रिपोर्ट के रूप में एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट के छिटपुट संदर्भों को अंतरिम रिपोर्ट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, इस तरह के संदर्भ का एकमात्र कारण यह था कि आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह (आई. एफ. आई. एन. के अलावा) में अन्य सहायक कंपनियों के मामलों की जांच चल रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में उक्त स्थिति की बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ संख्या 202 (VIII) और 202 (XII) में विवादित आदेश में सराहना की गई है।

3.26 इसके बाद, श्री बलबीर सिंह, विद्वान एसजी ने हमें एसएफआईओ आईएफआईएन रिपोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों पर ले गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, लेखा परीक्षकों पर आरोप लगाए गए हैं:

ए। आई. एफ. आई. एन. के प्रबंधन के साथ मिलीभगत और लेखा पुस्तकों को गलत साबित करने के लिए अधिनियम की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी;

बी। अधिनियम की धारा 143 और 147 के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता; और सी। वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष खाते को छिपाने के लिए सूचना/तथ्यों का दमन और अधिनियम की धारा 628 के साथ पठित धारा 211 और धारा 448 के साथ पठित धारा 129 के तहत एक गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच रिपोर्ट व्यापक रूप से दर्ज करती है कि लेखा परीक्षकों ने जानकारी के बावजूद आई. एफ. आई. एन. के संचालन में किसी भी वित्तीय असामान्यता की ओर इशारा नहीं किया और एक अपरिवर्तित राय दी जिसमें कहा गया कि वित्तीय विवरण भारत में स्वीकार किए गए लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

3.27 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच रिपोर्ट में, उधार और उपयोग के लेखा परीक्षा के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष हैं;

गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों का लेखापरीक्षा; ऋणों का लेखापरीक्षा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर, लेखा परीक्षकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 और आई. पी. सी. की धारा 417, 420 आर/डब्ल्यू 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 212 (14) के तहत जारी निर्देश और लेखा परीक्षकों के खिलाफ शुरू की गई शिकायत/अभियोजन को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

3.28 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया जाता है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 212 (14) के निर्देश और एस. एफ. आई. ओ. द्वारा दायर शिकायत को रद्द कर दिया है और शिकायत में शामिल अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा जारी रखने की अनुमति दी है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही को बरकरार रखते हुए एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और रद्द करने वाले विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और उक्त कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए, ताकि एन. सी. एल. टी. को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति मिल सके ताकि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार और भी कदम उठाए जा सकें।

विरोधी पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ:

4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, बी. एस. आर. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i) यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में बी. एस. आर. ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के अधिकारों को उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी), 20 और 21 का उल्लंघन करने के साथ-साथ असंवैधानिक और अमान्य होने के कारण चुनौती दी थी। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि
तथापि उच्च न्यायालय ने धारा 140 (5) की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पढ़ा है

ii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 140 (5) का उद्देश्य एक ऐसे लेखा परीक्षक को हटाना है जिसे न तो कंपनी द्वारा हटाया गया है, न ही कंपनी द्वारा। इस्तीफा दे दिया। यह आगे देखा गया है कि धारा 140 (5) के तहत एन. सी. एल. टी. की भूमिका केवल कंपनी के नियमों को बदलने की आवश्यकता की जांच करने के लिए है।

लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक को दंडित या प्रतिबंधित करने के लिए नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय के इस निवेदन को अस्वीकार करते हुए कि एन. सी. एल. टी. एक पारित कर सकता है अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत एक लेखा परीक्षक को 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 140 (5) के तहत एन. सी. एल. टी. का आदेश केवल कंपनी के लेखा परीक्षक को बदलने के लिए हो सकता है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि दूसरे परंतुक में प्रतिबंध के परिणाम स्वचालित रूप से इस तरह के परिवर्तन पर आते हैं और

एन. सी. एल. टी. के पास इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है।
iii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, बी. एस. आर. भी

एन. सी. एल. टी. के दो आदेशों को चुनौती दी, अर्थात् दिनांकित आदेश

09.08.2019 और दिनांकित आदेश 18.10.2019। ये दोनों आदेश एन. सी. एल. टी. द्वारा अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार शुरू की गई कार्यवाही में कथित रूप से पारित किए गए थे।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

और अधिनियम की धारा 212 के तहत दिनांकित 29.05.2019 निर्देश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी. एस. आर. ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत आदेश पारित करने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. एल. टी. ने धारा 140 (5) के आदेश के गुणागुण का निर्धारण नहीं किया है और एन. सी. एल. टी. ने अपने पहले आदेश में केवल

धारा 140 (5) की कार्यवाहियों की अनुरक्षण क्षमता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ नहीं जाती हैं

सभी गुणों में।

iv) अब जहां तक अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की व्याख्या और प्रयोज्यता का संबंध है, संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-मूल रिट याचिकाकर्ता हमें कंपनी अधिनियम के तहत लेखा परीक्षकों के विनियमन की योजना की ओर ले गए हैं और हमें विनियमन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की ओर ले गए हैं।

समय। v) यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 को पूरी तरह से पढ़ने से पता चलता है:

अधिनियम की धारा 140 (1) के लिए प्रक्रिया से संबंधित है

आई.

एक कंपनी द्वारा स्वैच्छिक लेखा परीक्षक।

140 (2) और (3) इस्तीफे की प्रक्रिया से निपटना।

ii.

एक लेखा परीक्षक।

धारा 140 (4) विशेष सूचना से संबंधित है। धारा 140 (5)

111 .

एन. सी. एल. टी. के आदेश द्वारा अनैच्छिक निष्कासन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 140 का शीर्षक (अर्थात्, "निष्कासन,

iv.

लेखा परीक्षक का त्यागपत्र और विशेष नोटिस देना) यह स्पष्ट करता है कि धारा 140 (5) केवल निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है -

लेखा परीक्षक को हटाना और लेखा परीक्षकों को अयोग्य ठहराने के लिए एक स्वतंत्र मूल प्रावधान नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि ए

शीर्षक एक संक्षिप्त नाम है जो सामूहिक रूप से एक [2023] 5 एस. सी. आर. द्वारा कवर की गई विषय वस्तु की विशेषताओं को इंगित करता है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

अनुभाग। रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

रायचूरमथम प्रभाकर बनाम के मामले में। रावतमल दुगर, (2004) 4 एस. सी. सी. 766 (पैरा 14)।

स्वीकार किया कि धारा 132, 141, 147, 245 और 447

धोखाधड़ी के मामलों में लेखा परीक्षक के दायित्व के साथ:

धारा 132 राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण ("एन. एफ. आर. ए.") के गठन का प्रावधान करती है। एन. एफ. आर. ए. को पर्याप्त शक्ति (नागरिक शक्तियों सहित) दी गई है।

अदालत) धारा 132 के तहत जुर्माना लगाने के लिए या

लेखा परीक्षक को पेशेवर या अन्य कदाचार के लिए एक लेखा परीक्षक (लेखा परीक्षक को प्रतिबंधित करने सहित) पर दंड। द.

धारा 132 के तहत स्पष्टीकरण शर्तों के लिए प्रदान करता है

" पेशेवर या अन्य कदाचार "का वही अर्थ होना जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के तहत निर्धारित किया गया है अधिनियम, 1949 ("सीए अधिनियम")। "पेशेवर या अन्य कदाचार" का अर्थ बहुत व्यापक है जैसा कि स्पष्ट किया गया है।

सी. ए. अधिनियम की अनुसूची I और II से। अतः यदि लेखा परीक्षक धोखाधड़ी या धोखाधड़ी में उकसाने के दोषी हैं, वे हैं

निश्चित रूप से पेशेवर दुराचार का दोषी, जिसके लिए

एन. एफ. आर. ए. के पास अयोग्य ठहराने, निलंबित करने की शक्तियाँ निहित हैं।

आदि। धारा 141 (3) (एच), जो विशेष रूप से लेखा परीक्षकों की पात्रता से संबंधित है, नियुक्ति के लिए अयोग्यता का प्रावधान करती है।

एक लेखा परीक्षक के मामले में ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है

धोखाधड़ी से जुड़ा अपराध। धारा 141 (3) (एच) लेखा परीक्षक को दोषी ठहराए जाने की तारीख से 10 साल के लिए अयोग्य ठहराती है।

धोखाधड़ी से जुड़ा अपराध। विशेष रूप से, जबकि

अंतर्निहित अपराध एक ही है, अर्थात्, एक ही धोखाधड़ी से जुड़ा एक कार्य, धारा 140 (5) और 141 (3) (एच) के तहत दंड अलग-अलग समय पर लगाया जाता है। एक स्थिति उत्पन्न हो सकता है जहाँ एक व्यक्ति के तहत अयोग्य माना जाता है

एन. सी. एल. टी. के अंतिम आदेश के माध्यम से धारा 140 (5)

बाद में धोखाधड़ी के आरोप से बरी

आपराधिक अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 447 के तहत तथ्यों का एक ही सेट। इसके अलावा जहां किसी व्यक्ति को धारा 447 के तहत दोषी ठहराया गया है, अगर वह पहले ही पीड़ित है

धारा 140 (5) के तहत 5 साल के लिए अयोग्यता के कारण उन्हें भारत में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए और अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

10 साल के लिए। इसलिए कुल अवधि 15 तक बढ़ सकती है।

धारा 147 (3) लेखा परीक्षकों पर पारिश्रमिक की वापसी या यहां तक कि नुकसान के रूप में वित्तीय दायित्व लगाती है जहां लेखा परीक्षक को अधिनियम की धारा 147 (2) के तहत दोषी ठहराया जाता है। धारा 147 (5) आपराधिक दायित्व के मामले में लेखा परीक्षा फर्मों और भागीदारों पर संयुक्त और कई दायित्व लगाती है।

धारा 241 (3) (ए) के सिविल परिणाम से संबंधित है

धोखाधड़ी और चिंता "किसी कंपनी के मामलों के संचालन और प्रबंधन से संबंधित कोई भी व्यक्ति"। इसमें निश्चित रूप से ऐसे लेखा परीक्षक शामिल होंगे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे किसी कार्य के संचालन और प्रबंधन से संबंधित हैं।

कंपनी के मामले। धारा 241 के तहत एक कार्यवाही में, एन. सी. एल. टी. निर्धारित करेगा: (i) क्या धोखाधड़ी हुई है; (ii) धोखेबाज कौन हैं; (iii) धोखाधड़ी में कौन शामिल था या जिसने उसे बढ़ावा दिया; और (iv) क्या पक्ष उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं। एन. सी. एल. टी. यह तय कर सकता है कि एक लेखा परीक्षक ने धोखाधड़ी में सांठगांठ की है और वह एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है धारा 242 (4 ए) के तहत जो निम्नलिखित प्रावधान करता है:

" 242. न्यायाधिकरण की शक्तियाँ। - (1) यदि, किसी भी आवेदन पर

धारा 241 के तहत बनाई गई, न्यायाधिकरण की राय है

(44) धारा 241 की उप-धारा (3) के संबंध में मामले की सुनवाई के समापन पर, न्यायाधिकरण अपना निर्णय दर्ज करेगा जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्यर्थी एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है या नहीं।

आचरण से जुड़ा अन्य कार्यालय और किसी अवधि के लिए किसी भी कंपनी के मामलों का प्रबंधन
[2023] 5 एस. सी. आर.

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

उक्त निर्णय की तारीख से पाँच साल: बशर्ते कि केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण की अनुमति से, ऐसे व्यक्ति को पांच साल की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले ऐसा कोई पद धारण करने की अनुमति दे सकती है।

99

यदि कोई व्यक्ति धारा 243 (1ए) के तहत एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं पाया जाता है, तो एनसीएलटी आदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति 5 साल तक किसी भी कंपनी के संचालन या प्रबंधन से जुड़े किसी भी पद पर नहीं रहेगा।

धारा 245 (1) (छ) (ii) एक लेखापरीक्षा फर्म सहित लेखापरीक्षकों के खिलाफ "उसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए विवरणों के अनुचित या भ्रामक बयान या किसी धोखाधड़ी, गैरकानूनी या गलत कार्य या आचरण के लिए एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे के माध्यम से हर्जाना या मुआवजे का आदेश देने का भी प्रावधान करती है। धारा 245 (2) एन. सी. एल. टी. को "कोई भी उपयुक्त कार्रवाई" करने की अनुमति देती है।

धारा 447 अपराधिक परिणामों से संबंधित है -

धोखाधड़ी। धारा 447 धोखाधड़ी के अपराध के लिए सजा निर्धारित करती है, अपराध स्वयं उक्त धारा के साथ जुड़े स्पष्टीकरण के माध्यम से बनाया गया है। अधिनियम की धारा 447 में प्रावधान है: " 447 , इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान सहित किसी भी दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

कुछ समय के लिए, कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं होगा, लेकिन जो धोखाधड़ी में शामिल राशि के तीन गुना तक बढ़ सकता है:

बशर्ते कि जहां विचाराधीन धोखाधड़ी में जनता शामिल हो

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए (i) किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय के मामलों के संबंध में "धोखाधड़ी" में कोई भी कार्य, चूक, छिपाना शामिल है।

भारत के किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी तथ्य या पद का दुरुपयोग।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

या कंपनी या उसके शेयरधारकों या उसके लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुँचाने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से किसी भी तरह से मिलीभगत करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह कंपनी में हो या नहीं। क्या कोई गलत लाभ या गलत नुकसान है:

((ख) "अनुचित लाभ" से संपत्ति के गैरकानूनी साधनों से लाभ अभिप्रेत है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से नहीं है।

हकदार है,

((ग) "अनुचित हानि" से संपत्ति के गैरकानूनी साधनों से होने वाली हानि अभिप्रेत है जिसके लिए खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है।

vii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 435 से 438 एक विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षण में एक प्रक्रिया प्रदान करती है।

सी. आर. पी. सी. की सुरक्षा। अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन के विपरीत एन. सी. एल. टी. के समक्ष पक्षों को दी जाने वाली सुरक्षा की तुलनात्मक योजना को दर्शाने वाला एक चार्ट।

viii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही धारा 140 (5) किसी लेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के कारण किसी दिए गए मामले में लागू न हो।

धारा 241 और 242 (4 ए) के साथ; और (डी) धारा 141 (3) (एच) के तहत अयोग्यता यदि लेखा परीक्षक धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है। इनमें से प्रत्येक कार्यवाही का परिणाम लेखा परीक्षक के लिए गंभीर है, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल है, और लेखा परीक्षक सजा से नहीं बचता है। ix) यह प्रस्तुत

किया जाता है कि धारा 140 (5) का परिचालन भाग एन. सी. एल. टी. को किसी कंपनी को अपने लेखा परीक्षक को "बदलने" का निर्देश देने का अधिकार देता है। एन. सी. एल. टी. इस शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि लेखा परीक्षक धोखाधड़ी से काम करने या धोखाधड़ी में उकसाने या मिलीभगत करने का दोषी है और उसने न तो इस्तीफा दिया है और न ही कंपनी द्वारा उसे हटाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह आदेश कि एन. सी. एल. टी. धारा 140 (5) के परिचालन भाग के तहत पारित कर सकता है, कंपनी के खिलाफ है न कि लेखा परीक्षक के। यह कंपनी के लिए एक आदेश है

अपने लेखा परीक्षक को बदलें और कोई अन्य आदेश नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शब्द [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"परिवर्तन" का अर्थ "दूसरे के साथ प्रतिस्थापन या विनिमय" और "एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए प्रतिस्थापन" माना गया है।

X) यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 (5) में दिए गए गैर-बाध्यकारी खंड के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. कंपनी को निर्देश दे सकता है।

और लेखा परीक्षक को हटाने वाला कोई और नहीं। गैर-बाध्यकारी खंड को उसमें दिए गए "परिवर्तन" शब्द के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 140 (5) में लागू नहीं हो सकती है।

जिन परिस्थितियों में लेखा परीक्षक को हटाने की मांग की गई थी, वे उस पद पर बने रहना बंद कर चुके हैं क्योंकि लेखा परीक्षक के इस्तीफे के बाद परिवर्तन का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रावधान की सरल भाषा से ही स्पष्ट है।

धारा 140 (5) के परिचालन भाग के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश और केंद्र सरकार को एक लेखा परीक्षक नियुक्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, जबकि मौजूदा लेखा परीक्षक का कार्य प्रतिबंधित है।

xii) इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 की उप-धारा 5 के दूसरे परंतुक में विचार किया गया है कि यदि इसके खिलाफ अंतिम आदेश पारित किया जाता है।

लेखा परीक्षक, तब लेखा परीक्षक आदेश पारित होने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरा परंतुक किसी पर विचार नहीं करता है।

एन. सी. एल. टी. द्वारा अलग आदेश। इसके बजाय, यह केवल एक स्वचालित परिणाम प्रदान करता है, अर्थात्, एक लेखा परीक्षक के लिए पाँच साल की अयोग्यता क्या है।

व्यक्ति या फर्म जिनके खिलाफ एन. सी. एल. टी. द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, पूरी फर्म को मिलता है।

अपने भागीदारों में से एक के कार्यों के लिए भी स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अवधि को बदलने के लिए एन. सी. एल. टी. को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

अयोग्यता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित प्रतिबंध कानून के संचालन द्वारा लगाया गया एक आंतरिक प्रावधान है, यदि कोई लेखा परीक्षक इस्तीफा नहीं देने का विकल्प चुनता है और भारत के आई. ओ. एन. और ए. एन. ओ. एन. वी. को मजबूर करता है।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

स्वयं पर प्रावधान के तहत एक अंतिम आदेश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे परंतुक की साधारण भाषा धारा 140 (5) के सक्रिय भाग के तहत पारित किए जा रहे अंतिम आदेश पर पूरी तरह से आधारित है।

xiii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तय किया गया कानून है कि जिन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है, वे अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होंगी और उनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। चूंकि धारा 140 (5) के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षक की अयोग्यता हो जाती है, इसलिए उसके तहत कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होगी। पेशेवर को अयोग्य ठहराना मृत्युदंड के समान है। इसलिए प्रमाण का मानक उचित संदेह से परे संतुष्टि है। एक अधिवक्ता बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (1989) सप्लीमेंट 2 एस. सी. सी. 25 (पैरा 4 (1) और (11) और आई. सी. ए. आई. बनाम। एल. के. रत्न और अन्य। (1986) 4 एससीसी 537 (पैरा 18)।

xiv) यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम को समग्र तरीके से पढ़ने और व्याख्या करने की आवश्यकता है। अधिनियम की योजना के तहत, यह धारा 447 है जो विशेष रूप से धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 140 (5) किसी लेखा परीक्षक को दंडित करने या दंडित करने का प्रावधान नहीं है। धारा 447 के बजाय धारा 140 (5) को धोखाधड़ी के लिए दंडित करने के प्रावधान के रूप में मानते हुए, मंत्रालय और एन. सी. एल. टी.

व्याख्या कि कुछ केवल कानून द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं। रिलायंस को धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। भारत संघ, (2019) 5 एससीसी 480 (पैरा

55) .

कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है और एक लेखा परीक्षक के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार को भौतिक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से धारा 140 (5) के तहत अपराध का निर्धारण एन. एफ. आर. ए. प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रदान किए गए बचाव और अपील की प्रक्रिया को निरर्थक और लेखा परीक्षकों के लिए केवल एक औपचारिकता बना सकता है।

xvi) यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल तभी होता है जब प्रावधानों की भाषा

एक कानून में स्पष्ट और स्पष्ट नहीं हैं, उसी [2023] 5 एस. सी. आर. का उद्देश्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रावधान की व्याख्या करने के लिए अदालत द्वारा जांच की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्यपूर्ण पर सादे भाषा की व्याख्या की प्रधानता के संबंध में कानून के निम्नलिखित सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं।

व्याख्या:

आई.

अदालतों को अब यह मानने के लिए बहुत अनिच्छुक होना चाहिए कि

संसद ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे कुछ हासिल नहीं किया है, जबकि यह स्पष्ट है कि संसद क्या चाहती थी।

हासिल करें। [डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम देखें। मुख्यमंत्री और अन्य, (2021) 8 एस. सी. सी. 1 (पैरा 150)।

इसलिए अदालतें उस निर्माण को अस्वीकार कर देंगी जो

ii.

यह विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा, भले ही उपयोग की गई भाषा में कुछ सटीकता हो। [जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर) (पैरा) देखें।

151) .

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या तभी दी जा सकती है जब

iii.

वैधानिक प्रावधानों की भाषा में कुछ अस्पष्टता है या यह बेतुके परिणामों की ओर ले जाता है। [महाराष्ट्र राज्य बनाम देखें। श्री विले पार्ले केलवानी मंडल और

ओआरएस। (2022) 2 एससीसी 725 (पैरा 16)।

xvii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, इस न्यायालय ने समय-समय पर संदिग्ध दंड के सिद्धांत को बरकरार रखा है, जिसके लिए आवश्यक है कि "यदि दो विचार और उचित निर्माण किसी प्रावधान पर रखे जा सकते हैं, तो अदालत को उस निर्माण के पक्ष में झुकना चाहिए जो विषय को दंड से छूट देता है न कि एक जो जुर्माना लगाता है"। रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

एस. ई. बी. आई. के मामले बनाम सुनील कृष्ण खेतान (2023) 2 एस. सी. सी. 643 (पैरा 55) और तोलाराम रेलुमल बनाम। बम्बई राज्य। (1955) 1 एस. सी. आर. 158 (पैरा 8)।

xviii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत NCLT का अधिकार क्षेत्र किसी कंपनी के मौजूदा लेखा परीक्षक को हटाने का निर्देश देना और केंद्र सरकार द्वारा उसके प्रतिस्थापन की अनुमति देना है। यह है।

प्रस्तुत किया कि किसी भी व्यक्ति/फर्म को उस पद से हटाना संभव नहीं है जो मट्टा धारण नहीं कर रहा है। तदनुसार, आई. एफ. आई. एन. के लेखा परीक्षक के रूप में पहले ही इस्तीफा दे चुके बी. एस. आर. को हटाने का आदेश

बी. एस. आर. को आई. एफ. आई. एन. का लेखा परीक्षक बने रहने के रूप में मानने की कानूनी कल्पना के माध्यम से ही संभव होगा।

भारत का आयन और एक अन्य बनाम। डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

xix) इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 140 (5) कोई कानूनी कल्पना पैदा नहीं करती है जिसके द्वारा एक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा दे दिया हो।

लेखा परीक्षक के रूप में व्यवहार किया जाना जारी रहेगा। एक काल्पनिक कल्पना केवल विधायिका द्वारा बनाई जा सकती है। वास्तव में, अदालतों और न्यायाधिकरणों के पास न्यायिक द्वारा एक काल्पनिक कल्पना बनाने की शक्ति नहीं है

व्याख्या जब कानून इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। भुवाल्का के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया जाता है।

स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम यू. ओ. आई. (2017) 5 एस. सी. सी. 598 (पैरा 38) और संत लाल गुप्ता बनाम। आधुनिक सहकारी आवास सोसायटी

(x) यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी पूर्व लेखापरीक्षक को हटाने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि धारा 140 का उद्देश्य और उद्देश्य, यानी लेखा परीक्षकों को हटाना और बदलना, लेखा परीक्षक के इस्तीफे से संतुष्ट हो गया है। ऐसे पूर्व लेखा परीक्षक पर, उनके इस्तीफे के बावजूद, अधिनियम की धारा 447 के तहत धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, धारा 140 (5) के तहत लेखा परीक्षक को हटाने का सवाल नहीं उठ सकता है और न ही उठ सकता है। xxi) यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंत्रालय इस बात से अवगत था कि धारा 140 (5) के तहत एक पूर्व लेखा परीक्षक के खिलाफ एक काल्पनिक उपकरण के अलावा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह बात स्पष्ट है।

140 (5) कंपनी याचिका के प्रार्थना (ए), (बी) और (सी) से डेलॉयट से अनुरोध किया गया था जिसमें मंत्रालय ने डेलॉयट को "मानित हटाने" की मांग की थी, भले ही वह पहले ही लेखा परीक्षक के रूप में बाहर हो चुका था। नतीजतन, एन. सी. एल. टी. 140 (5) कंपनी याचिका के गुण-दोष में नहीं जा सकता था क्योंकि मांगी गई राहत एन. सी. एल. टी. की शक्तियों से परे थी।

धारा 140 (5), पिछले लेखा परीक्षकों को हटाने का निर्देश नहीं दे सकती है या ऐसे लेखा परीक्षकों को पिछली तारीख को हटा दिया गया है। एन. सी. एल. टी., एक कानून की रचना होने के नाते, क्षेत्र के भीतर कार्य करना पड़ता है। कानून/वैधानिक प्रावधान द्वारा निर्धारित। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. [2023] 5 एस. सी. आर. नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों में कथित परिवर्तन का निर्देश देकर ऐसी शक्ति का प्रयोग करें जो उसमें स्पष्ट रूप से निहित नहीं है। बी. हिम्मतलाल अग्रवाल बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 2804 (पैरा 8) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। भारत संघ, (2003) 3 एस. सी. सी. 186 (पैरा 20-21)।

xiv) यह प्रस्तुत किया गया है कि पासुपुलेती वेंकटेश्वरलु v. मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स, (1975) 1 एस. सी. सी. 770, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक कार्यवाही पोस्ट फाइलिंग घटना के कारणों से बनाए रखने योग्य नहीं हो सकती है। इस न्यायालय ने कहा, "यदि एल. आई. एस. के अदालत में आने के बाद उत्पन्न होने वाला कोई तथ्य और उसे ढालने के तरीके के लिए राहत के अधिकार पर मौलिक प्रभाव पड़ता है, तो उसे ट्रिब्यूनल के संज्ञान में लगन से लाया जाता है, तो वह उस पर पलक नहीं झपक सकता है या उन घटनाओं के प्रति अंधा नहीं हो सकता है जो अपमानजनक उपचार को बाधित या अक्षम बनाती हैं।"

खंड और इसे फिर से लिखने की आवश्यकता होगी। ऐसा निहित प्रावधान धारा 140 (5) के उद्देश्य के विपरीत भी होगा क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि एक लेखा परीक्षक जिसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप हैं: लेखा परीक्षक के रूप में जारी रखा गया है और उसे इस्तीफा देने की अनुमति नहीं है। जब तक एन. सी. एल. टी. धारा 140 (5) के पहले परंतुक के तहत अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश पारित नहीं करता, तब तक धोखाधड़ी करने के बावजूद, यह एक लेखा परीक्षक को जारी रखने के लिए मजबूर करने की एक विसंगत स्थिति पैदा करेगा।) मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 (5) अत्यधिक और स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह एन. सी. एल. टी. को निर्देशित और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान करती है और वह भी एक संक्षिप्त कार्यवाही में, धोखाधड़ी के गंभीर अपराध और गंभीर के साथ अनिवार्य अयोग्यता के परिणाम के निर्धारण के लिए।

नागरिक मृत्यु के समान परिणाम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंड

लेखा परीक्षकों और भारत के आई. ओ. एन. और ए. एन. डी. एच. आर. वी. की स्वतः अयोग्यता के रूप में।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 140 (5) के तहत परिकल्पित पूर्व निर्धारित अवधि के लिए पूरी तरह से असंबद्ध और निर्दोष भागीदारों सहित पूरी फर्म अत्यधिक असमान है और कम से कम आक्रामक तरीका नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 (5) एक स्वचालित जुर्माना बनाती है।

अयोग्यता का, संक्षिप्त निर्णय पर, जब धारा 435 के तहत मुकदमे की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम की धारा 141 (3) (एच) के तहत इस तरह के दंड का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

446 अधिनियम से। इसके परिणामस्वरूप दोहरे खतरे के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और संविधान के अनुच्छेद 20 (2) का उल्लंघन होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अयोग्यता "नागरिक मृत्यु" के समान है धारा 140 (5) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी के अनुसार बी. एस. आर. और उसके भागीदारों के अपने पेशे को जारी रखने के मौलिक अधिकार को बाधित करती है। वही, अनुचित होने के कारण, गिरता नहीं है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (6) के संरक्षण के भीतर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 (5) को उसकी सरल भाषा में लागू करना।

अर्थात्, लेखा परीक्षकों के परिवर्तन से इसे उपरोक्त गंभीर स्थिति से बचाया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम के तहत लेखा परीक्षकों को "हुक से बाहर" किए बिना संवैधानिक उल्लंघन। (xviii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. एल. टी. ने अपने पहले आदेश के माध्यम से, बी. एस. आर. सहित आई. एफ. आई. एन. के पूर्व लेखा परीक्षकों के खिलाफ 140 (5) कंपनी याचिका को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को गलत तरीके से बरकरार रखा, इस आशय के किसी भी कानून या ऐसा करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र और शक्ति के अभाव में गलत तरीके से एक काल्पनिक कल्पना बनाई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

एन. सी. एल. टी. ने गलत तरीके से यह अभिनिर्धारित करते हुए अधिकारिता ग्रहण की कि उसे पूर्व लेखा परीक्षकों के मानित परिवर्तन के लिए निर्देश पारित करने का अधिकार था और इसलिए एन. सी. एल. टी. का पहला आदेश धारा 140 (5) के विपरीत है क्योंकि यह अधिकारिता के बिना पारित किया गया था और एक गलत धारणा पर आधारित था कि अधिकारिता तथ्य कि कंपनी के मौजूदा लेखा परीक्षकों को "बदलने" की आवश्यकता थी। XXX) यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक साधारण कानून है कि एक "क्षेत्राधिकार तथ्य" एक अनिवार्य या अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार की धारणा के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। न्यायालय अधिकारिता संबंधी तथ्य का निर्णय न करके या गलती से निर्णय लेकर गलती से अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता है। के निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है

कैरोना लिमिटेड बनाम के मामलों में यह न्यायालय। पार्वती स्वामीनाथन एंड संस (2007) 8 एस. सी. सी. 559 (पैरा 27,28,36) और अरुण कुमार बनाम। भारत संघ, (2007) 1 एस. सी. सी. 732 (पैरा 74-76)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि मूलभूत तथ्य

अनुमान लगाने से पहले इसे स्थापित किया जाना चाहिए।

5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बलराम गर्ग के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया

बी. एस. ई. बी. आई., (2022) 9 एस. सी. सी. 425 (पैरा 45 और 51)।

XXX) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 140 (5) के पहले प्रावधान के तहत आई. एफ. आई. एन. के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में एम. एम. सी. की नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन पर एन. सी. एल. टी. का दूसरा आदेश भी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब बी. एस. आर. ने लेखा परीक्षक के रूप में इस्तीफा दे दिया, तो इसका कोई सवाल ही नहीं था।

धारा 140 (5) के पहले परंतुक के तहत रहे हैं क्योंकि सबसे पहले, धारा 140 (5) स्वयं पिछले लेखा परीक्षकों पर लागू नहीं होती थी, और इसलिए पहले परंतुक को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था; दूसरा, पहला परंतुक केवल धारा 140 (5) के तहत अधिकार क्षेत्र के आदेश के लंबित रहने तक एक अस्थायी उपाय है; तीसरा, एन. सी. एल. टी. का दूसरा आदेश अस्थायी आदेश की प्रकृति में नहीं है; चौथा, एक बार अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, केवल केंद्र सरकार पहले के तहत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या उन्हें बदलने के लिए अधिकृत है। प्रावधान। धारा 140 (5) के पहले परंतुक के तहत, केंद्र सरकार को तात्कालिकता के कारण लेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति दी गई है।

अपनी पसंद का लेखा परीक्षक नियुक्त करने की संबंधित कंपनी की शक्ति को नहीं छीनना; पाँचवाँ, बी. एस. आर. ने स्वीकार किया कि पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

और अपना पद खाली कर दिया, जैसा कि मंत्रालय ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों में स्वीकार किया और इस न्यायालय ने दिनांकित 26.09.2019 आदेश में इसका उल्लेख किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा, मंत्रालय ने दाखिल करने के समय एन. सी. एल. टी. से विभिन्न प्रमुख तथ्यों को रोक दिया था।

4.1 अब जहाँ तक धारा 212 (14) और धारा 212 (15) के तहत जारी निर्देश का संबंध है, यह निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है:

सरकार; ii) धारा 212 (11) में प्रावधान है कि यदि एस. एफ. आई. ओ. को ऐसा करने का निर्देश दिया जाता है तो एस. एफ. आई. ओ. को केंद्र सरकार को एक "अंतरिम रिपोर्ट" प्रस्तुत करनी होगी।

तो केंद्र सरकार द्वारा; भारत का संघ और एक और v.

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

iii) धारा 212 (12) के तहत एस. एफ. आई. ओ. को "जांच पूरी होने" पर ही केंद्र सरकार को "जांच रिपोर्ट" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, जांच पूरी होने से पहले किसी भी समय "जांच रिपोर्ट" प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, जबकि धारा 212 (11) के तहत "अंतरिम रिपोर्ट" किसी भी स्तर पर प्रस्तुत की जा सकती है।

iv) धारा 212 (14) के तहत, केंद्र सरकार को एस. पी. आई. ओ. को किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। कंपनी या उसके अधिकारी, यदि केंद्र सरकार इस पर विचार करती है

केवल धारा 212 (12) के तहत जारी "जांच रिपोर्ट" की जांच के बाद आवश्यक है, यानी जांच पूरी होने के बाद। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय बनाम राहुल मोदी (2019) 5 एस. सी. सी. 266 (पैरा 30) के मामले में रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। v) धारा 212 (14) केंद्र सरकार को "जांच रिपोर्ट" की जांच करते समय कानूनी सलाह लेने की अनुमति देती है, जो स्वयं "जांच" शब्द को रंग देती है और दर्शाती है कि केंद्र सरकार को "जांच" के लिए अपना दिमाग ठीक से लगाना है।

vii) धारा 212 (15) के तहत, यह केवल "जांच रिपोर्ट" है (केवल जांच पूरी होने पर प्रस्तुत की जाती है जो दायर की जाती है। विशेष न्यायालय के साथ पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट मानी जाती है

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत। (सी. एच. पी. सी.) महत्वपूर्ण रूप से, धारा 212 (15) एक काल्पनिक कल्पना है जो केवल धारा 212 (12) के तहत जांच रिपोर्ट बनाने तक सीमित है, जो धारा 173, सी. आर. पी. सी. के तहत पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट होगी।

viii) इसलिए यह स्पष्ट है कि विधायिका ने अपने विशिष्ट उद्देश्य के साथ दो अलग-अलग प्रकार की रिपोर्टों की परिकल्पना की है। सबसे पहले रिपोर्ट का प्रकार धारा 212 (11) के तहत है। कौन सी रिपोर्ट एक 'अंतरिम रिपोर्ट' है और पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी समय जारी की जा सकती है [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. एफ. आई. ओ. द्वारा जाँच। दूसरे प्रकार की रिपोर्ट एक 'जांच रिपोर्ट' है जो एस. एफ. आई. ओ. द्वारा जांच पूरी होने के बाद ही जारी की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा अभियोजन शुरू करने के उद्देश्यों के लिए धारा 212 (14) के तहत केवल 'जांच रिपोर्ट' पर विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर, एन. सी. एल. टी. के समक्ष धारा 212 (14 ए) के तहत जांच रिपोर्ट या उसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

यहां तक कि अंतरिम रिपोर्ट भी;

212 (14) अपने दिमाग को लागू करने, कानूनी राय लेने (यदि आवश्यक हो) और उसके बाद ही यह तय करना आवश्यक है कि कोई मंजूरी आदेश है या नहीं जारी किया जाए, अर्थात्, यदि उसकी राय में "जांच रिपोर्ट" के आधार पर अभियोजन शुरू किया जाना है। इसके अलावा, केवल ऐसी 'जांच रिपोर्ट', जिस पर केंद्र सरकार द्वारा धारा 212 (14) के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए विचार किया जाता है, धारा 173, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट होनी चाहिए।

x) यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, एस. एफ. आई. ओ. की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट एक "अंतरिम रिपोर्ट" है और "जांच पूरी होने" पर जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार, 2 अंतरिम रिपोर्ट अधिनियम की धारा 212 (12) के तहत एक "जांच रिपोर्ट" नहीं है और हो सकता है

केंद्र सरकार द्वारा धारा 212 (14) के तहत प्रतिबंध आदेश जारी करने के उद्देश्यों के लिए विचार नहीं किया गया है; xi) वर्तमान मामला मंजूरी की अयोग्यता/अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि बिना किसी मंजूरी का मामला है, क्योंकि मंजूरी के लिए पूर्व-अपेक्षित, यानी अंतिम जांच रिपोर्ट, अनुपस्थित है;

xii) जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, जहां एक जांच रिपोर्ट स्वयं कहती है कि जांच अधूरी है या आगे सबूत एकत्र किया जाना बाकी है, तो ऐसी जांच रिपोर्ट कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है और इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है। पी. एम. सी. मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामलों में रिलायंस को निम्नलिखित निर्णयों पर रखा गया है। राज्य 2014 (3) एम. डब्ल्यू. एन. (करोड़) 454 (पैरा 11 और 19); प्रवीण चंद्र मोदी बनाम राज्य का

आंध्र प्रदेश, क्र. ऐप. सं. 49,1964; हरि चंद और राम पाल बनाम। राज्य सीआरएल। विविधा (एम) 1977 का 99 और 111 (पैरा 14)। तदनुसार, पैरा 1.5 और 4.126 की भाषा दी गई है। 1 में से

2 एन. डी. अंतरिम एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कभी भी धारा 212 (12) के तहत एक जांच रिपोर्ट के रूप में नहीं माना जा सकता है; भारत का आई. ओ. एन. और ए. एन. ओ. एन. वी.

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

xiii) दूसरी अंतरिम रिपोर्ट की जांच करते समय भी एम. सी. ए. का विचार था कि दूसरी अंतरिम रिपोर्ट पूरी नहीं थी।

आई. एफ. आई. एन. के संबंध में जांच रिपोर्ट। तदनुसार, मंत्रालय ने एस. एफ. आई. ओ. को उन पहलुओं पर आगे की जांच करने का निर्देश दिया था जो पहले से ही दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में शामिल थे।

xiv) इसके अलावा, मंत्रालय और एस. एफ. आई. ओ. ने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, प्रतिबंध आदेश के पैरा V की व्याख्या करने के लिए कोई हलफनामा या तर्क दर्ज नहीं किया या यह कि जांच पूरी हो गई थी और दूसरी अंतरिम रिपोर्ट को मंत्रालय द्वारा अंतरिम रिपोर्ट के रूप में नहीं माना गया था। एस. एफ. आई. ओ. इससे बच नहीं सकता।

शपथ पत्र दाखिल न करने के परिणाम, शपथ पर बताते हुए, कि जांच पूरी नहीं हुई थी। यह तथ्य का सवाल है;

xv) धारा 212 (12), एक रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन शुरू करने की अनुमति नहीं देती है जो तब तक जारी की जाती है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है।

पूरा किया। यह धारा 212 (12), (14) और (15) के संयुक्त पठन से स्पष्ट है। इसके अलावा, हालांकि सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत एक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच पर विचार किया गया है।

धारा 173 (2) में कहा गया है कि धारा 173 (8) निरीक्षक को अपूर्ण या प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और बाद में प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं बनाती है।

एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर। कमल लोचन सेन बनाम के मामलों में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया है। उड़ीसा राज्य (1982) 54 सी. एल. टी. 509 (पैरा 5) और ए. वी. धर्म रेड्डी बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य, 2011 क्रिएलजे 185 (पैरा 5)। इसलिए, रणनीति

एस. एफ. आई. ओ. और मंत्रालय द्वारा "अंतरिम रिपोर्ट" के आधार पर कार्रवाई करने और साथ ही आगे की जांच करने के लिए अपनाया गया कदम अवैध है।

xvii) प्रतिबंध आदेश प्रासंगिक सामग्री और साक्ष्य पर ध्यान दिए बिना पारित किया गया था; xviii) धारा 212 (14) में केंद्र सरकार द्वारा "जांच" की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो "कानूनी सलाह" लेने पर भी विचार किया गया है। संसद देखभाल की एक बेहतर डिग्री निर्धारित करती है जो [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 212 (14) के तहत आदेश पारित करते समय इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए, केंद्र सरकार का निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए और उचित दिमाग के साथ किया जाना चाहिए।

xiX) कानून में, मंजूरी के आदेश को सामग्री की पर्याप्तता के साथ-साथ मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक तथ्यों, सामग्री और साक्ष्य दोनों पर विचार करने का खुलासा करना चाहिए। मुकेशभाई विठ्ठलदास चौहान बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। गुजरात राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 622 (पारस 17,18 और 19);

x) एस. एफ. आई. ओ. ने 28.05.2019 पर दूसरी अंतरिम एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट प्रस्तुत की। मान लीजिए, रिपोर्ट में 32,000 से अधिक पृष्ठ शामिल थे, जिसमें रिपोर्ट का मुख्य भाग लगभग 787 पृष्ठों का था। 2 अंतरिम एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट की कथित तौर पर एक प्रक्रिया द्वारा जांच की गई थी। अधिकारी (कानूनी अनुभाग), मंत्रालय जिन्होंने एक प्रसंस्करण नोट तैयार किया था। यह प्रोसेसिंग नोट कथित तौर पर तत्काल प्राथमिकता के आधार पर 'वरिष्ठ अधिकारी' को प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त आंतरिक प्रक्रियाओं के बावजूद, मंत्रालय ने 29.05.2019 (यानी,

ईमेल दिनांकित 01.10.2019, 10.10.2019, और 14.10.2019। बंबई उच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना सही था क्योंकि मंत्रालय और एस. एफ. आई. ओ. उचित प्रदर्शन करने में विफल रहे। किसी भी दस्तावेज़ या शपथ पत्र के माध्यम से दिमाग का आवेदन;

xxi) दूसरी अंतरिम एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट की विशाल प्रकृति और आंतरिक प्रक्रियाओं को देखते हुए, मंत्रालय के लिए प्रतिबंध आदेश जारी करने से एक दिन पहले दूसरी अंतरिम एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट (अधिनियम की धारा 212 (14) के तहत आवश्यक) की जांच करना और उस पर अपना दिमाग लगाना असंभव था। ऊपर वर्णित घटनाएँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि प्रतिबंध आदेश जल्दबाजी में, बिना सोचे-समझे और बाहरी विचार के लिए दिया गया था। इस प्रकार, इस तरह के प्रतिबंध आदेश का पालन करने वाली कार्यवाही भी दूषित हो जाती है। के. के. मिश्रा बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 676 (पैरा 18) और अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जडेजा बनाम। गुजरात राज्य (1995) 5 एस. सी. सी. 303 (पैरा 15);

xxii) इसके अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में मंत्रालय की विफलता कि उसके अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से भारत संघ और अन्य पर अपना दिमाग लगाया।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

दूसरी अंतरिम एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट भी सिद्धांतों के विपरीत है।

प्रकटीकरण के कर्तव्य से संबंधित क्योंकि प्रकटीकरण कार्यवाही की निष्पक्षता की रक्षा करेगा और प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी बढ़ाएगा। रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है

T.Takano v का मामला। एस. ई. बी. आई. (2022) 8 एस. सी. सी. 162 (पैरा 62.3);

xxiii) इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिबंध आदेश कानूनी रूप से खराब है और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से रद्द कर दिया है; xiv) अधिकार क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त एक वैध मंजूरी का अस्तित्व है। इसलिए अभियोजन अक्षम हो जाता है

और परिणामस्वरूप कार्यवाही दूषित हो जाती है और बिना

अधिकारिता जहाँ कोई वैध मंजूरी नहीं दी जाती है। रिलायंस को रखा गया है

गोकुलचंद द्वारकादास के मामलों में निर्णयों पर

मोरारका बनाम। राजा, (1947-48) 75 IA 30; यूसुफल्ली मुल्ला नूबभाँय बनाम। राजा, 1949 क्रि एल. जे. 889 (पैरा 15); मोहम्मद। इकबाल अहमद बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (1979) 4 एस. सी. सी. 172 (पैरा 3);

XXV) धारा 212 (14) के तहत एम. सी. ए. द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश अमान्य और गैर-अनुमानित है। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. एफ. आई. ओ. द्वारा शुरू किया गया अभियोजन किसी भी मंजूरी से अनुपस्थित है और इसलिए

एक शून्य और बिना किसी अधिकार क्षेत्र के।

4.2 आपराधिक अपील सं. 2300/2011-हरि शंकरन में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने आगे कहा है कि वर्तमान मामले में कोई अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं है।

एस. एफ. आई. ओ. क्वा हरि शंकरन द्वारा दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी रिपोर्ट हरि शंकरन की अंतिम जांच रिपोर्ट की प्रकृति में नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि दूसरी रिपोर्ट अंतिम जांच नहीं थी हरि शंकरन की रिपोर्ट के अनुसार, विचाराधीन अभियोजन के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था और इसलिए परिणामस्वरूप हरि शंकरन की शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती थी।

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा वर्तमान अपीलों को खारिज करने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया जाता है।

संविधान की धारा 140 (5) का विश्लेषण और व्याख्या

कंपनी अधिनियम, 2013:

5. अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) "लेखा परीक्षक को हटाना, इस्तीफा देना और विशेष सूचना देना" शीर्षक से एस. सी. आर. (2023) 5 के अध्याय 10 में दिखाई देती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रावधान है कि लेखा परीक्षक प्रबंधन सेवाओं सहित कुछ सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा सेवाओं के दायरे से बाहर इसकी किसी भी गतिविधि से अप्रभावित एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए। लेखा परीक्षक को प्रतिबंधित किया गया है कंपनी को कोई भी प्रबंधन सेवा प्रदान करना। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 144 के तहत बनाया गया निषेध और प्रतिबंध मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए है।

विचाराधीन कंपनी और अन्य हितधारकों जैसे ऋणदाताओं और निवेशकों और बड़े पैमाने पर जनता का हित।

भारत संघ और ए. एन. डी. एच. वी. को ध्यान में रखते हुए। डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

उपरोक्त प्रावधान और पृष्ठभूमि में अंतर्निहित सार्वजनिक नीति,

और अधिनियम की धारा (3) लेखा परीक्षकों के इस्तीफे से संबंधित है और अधिनियम की धारा 140 (4) सेवानिवृत्त होने वाले लेखा परीक्षक के अलावा एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए एजीएम में विशेष नोटिस देने और उस संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। हालांकि, अधिनियम की धारा 140 (5) न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को, या तो स्वतः सज्जान लेते हुए या केंद्र सरकार या किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, लेखा परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

धोखाधड़ी के तरीके से कार्य करना या किसी कंपनी के प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी में उकसाना या मिलीभगत करना। यदि किसी जांच के पूरा होने पर न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की है, तो वह आदेश द्वारा कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश दे सकता है। इसलिए, धारा 140 (5) के पहले भाग में एन. सी. एल. टी. की शक्तियां अर्ध-न्यायिक प्रकृति की हैं और न्यायाधिकरण के पास लेखा परीक्षकों की भूमिका की जांच करने और उनके धोखाधड़ीपूर्ण आचरण और उनके कार्य के त्याग पर निर्णय लेने के लिए एक दीवानी अदालत की शक्तियां होंगी। धारा 140 (5) का पहला परंतुक शक्ति प्रदान करता है - केंद्र सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायाधिकरण और यदि न्यायाधिकरण का समाधान हो जाता है कि लेखा परीक्षक के किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो ऐसे लेखा परीक्षक को हटाने और/या एक आदेश पारित करने के लिए कि ऐसा लेखा परीक्षक (ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर) लेखा परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा और केंद्र सरकार उसके स्थान पर दूसरे लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है। इस प्रकार, धारा 140 (5) के पहले परंतुक के तहत शक्तियों को अंतरिम या अस्थायी उपाय कहा जा सकता है ताकि किसी मौजूदा लेखा परीक्षक को जारी रखने से रोका जा सके और उसे प्रथम दृष्टया संतुष्टि के आधार पर एक लेखा परीक्षक के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके कि धोखाधड़ी की गई है और जब परिस्थितियां प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती हैं। इस तरह के आदेश को विस्तृत जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी निलंबन के समान एक अंतरिम आदेश कहा जा सकता है।

5.3 अधिनियम की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक में आगे यह प्रावधान किया गया है कि एक लेखा परीक्षक, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, जिसके खिलाफ अंतिम आदेश धारा 140 (5) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया व्यक्ति पांच साल [2023] की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक को एक मूल प्रावधान कहा जा सकता है और यह धारा 140 (5) (प्रथम भाग) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश पर काम करता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कंपनी विधेयक, 2009 के संबंध में पिछली स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद और विभिन्न हितधारकों की सिफारिशों के साथ कंपनी विधेयक, 2011 पेश किया गया। 2009 के विधेयक के खंड 123 (1) के लिए स्थायी समिति का सुझाव (जिसमें धोखाधड़ी का पता चलने पर एन. सी. एल. टी. द्वारा एक लेखा परीक्षक को हटाने का प्रावधान किया गया था) प्रावधान को और अधिक कठोर बनाने के लिए था; और एक लेखा परीक्षक के लिए परिणाम प्रदान करने के लिए जब ऐसा लेखा परीक्षक धोखाधड़ी कर रहा था और एन. सी. एल. टी. द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी के लिए हटा दिया जाता है। अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के दूसरे प्रावधान के माध्यम से भी ऐसा ही किया गया है। इसलिए, धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक, जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक ठोस प्रावधान है, एक विस्तृत विश्लेषण के बाद और स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और प्रावधान को और अधिक कठोर बनाने और प्रावधान करने की दृष्टि से पेश किया गया है।

एक लेखा परीक्षक के लिए परिणाम जब ऐसे लेखा परीक्षक को पाया जाता है धोखाधड़ी करना और ऐसी धोखाधड़ी के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा हटा दिया जाता है। यह है।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा धारा 140 (5) के पहले भाग के तहत अंतिम आदेश पारित करने पर और यदि कोई लेखा परीक्षक धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या कंपनी के प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है, तो धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए परिणाम अनुसरण करेंगे। इसलिए, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक को आकर्षित करने से पहले, धारा 140 (5) के पहले भाग के अनुसार किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के खिलाफ एक विस्तृत जांच होनी चाहिए और एन. सी. एल. टी. द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है या कंपनी या उसके द्वारा या उसके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की है।

निदेशक या अधिकारी।

6. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, हालांकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की शक्तियों को बरकरार रखा है, हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार जब लेखा परीक्षक एक लेखा परीक्षक के रूप में इस्तीफा दे देता है या अपने इस्तीफे पर लेखा परीक्षक नहीं रहता है, तो उसके बाद धारा 140 (5) की कार्यवाही अब बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि भारत संघ द्वारा दायर याचिका

धारा 140 (5) के तहत लेखा परीक्षक के बाद के इस्तीफे से संतुष्ट हो गया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भारत और ए. एन. डी. ए. वी. का पूरी तरह से गलत है।

डीलोइट हैस्किस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

और अस्थिर है। के बाद एक लेखा परीक्षक का इस्तीफा

धारा 140 (5) के तहत दायर किया गया आवेदन धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगा। लेखा परीक्षक के इस्तीफे और/या हटाने को धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही का अंत नहीं कहा जा सकता है। धारा 140 (5) की कार्यवाही के तहत जांच की परिणति और एक लेखा परीक्षक के आचरण पर न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर भी आगे के परिणाम हैं, चाहे ऐसे लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया हो या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया हो या मिलीभगत की हो, जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किया गया है। इसलिए, धारा 140 (5) के पहले भाग के तहत शुरू की गई जांच/कार्यवाही को अपने तार्किक अंत तक जाना होगा और बाद में एक लेखा परीक्षक का इस्तीफा और/या बंद करना धारा 140 (5) के तहत जांच/कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगा। यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या कि एक बार लेखा परीक्षक के इस्तीफा देने के बाद, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है और अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो उस मामले में, एक लेखा परीक्षक अंतिम आदेश से बचने के लिए और धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए अंतिम आदेश के परिणाम से इस्तीफा दे सकता है और न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी अंतिम आदेश से बच सकता है। विधायिका का इरादा ऐसा नहीं हो सकता।

6.1 जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक एक ठोस प्रावधान है, हालांकि यह एक

परंतुक, और वही धारा 140 (5) के पहले भाग में न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर काम करेगा और/या निर्भर करेगा। यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या कि बाद में इस्तीफे पर

और/या किसी लेखा परीक्षक का बंद होना, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है और/या केंद्र सरकार द्वारा धारा 140 (5) के तहत याचिका अब बनाए रखने योग्य नहीं है, उस मामले में, धारा 140 (5) का दूसरा परंतुक निरर्थक हो जाएगा और किसी भी मामले में धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई ऐसी व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो उस मामले में, धारा 140 (5) में दूसरे परंतुक को शामिल करने का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा। धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक का उद्देश्य और उद्देश्य, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रावधान को और अधिक कठोर बनाना और एक लेखा परीक्षक के लिए परिणाम प्रदान करना है जब ऐसा लेखा परीक्षक धोखाधड़ी कर रहा होता है और उसे ऐसी धोखाधड़ी के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा हटा दिया जाता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जा रहे अंतिम आदेश पर धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत लेखा परीक्षक/फर्म ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से [2023] 5 एस. सी. आर. में कार्य किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखाधड़ी के तरीके से या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों द्वारा या उनके संबंध में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत की गई, वह पांच साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक में प्रयुक्त "कोई भी" शब्द महत्वपूर्ण है। न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने पर, ऐसे लेखा परीक्षक को न केवल कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में हटा दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा, बल्कि ऐसा लेखा परीक्षक/फर्म भी पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।

7. इसलिए, अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की सही व्याख्या और योजना पर, एक बार जब अधिनियम की धारा 140 (5) के पहले भाग के तहत जांच/कार्यवाही शुरू की जाती है, या तो न्यायाधिकरण द्वारा या केंद्र सरकार या किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, यह अपने तार्किक अंत तक आना चाहिए और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसी जांच/कार्यवाही के दौरान लेखा परीक्षक ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं, न्यायाधिकरण द्वारा एक अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे लेखा परीक्षक ने वास्तव में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धोखाधड़ी से काम किया है या नहीं। कंपनी को धारा 140 (5) के पहले भाग में दिए गए अपने लेखा परीक्षक को बदलने का निर्देश केवल न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का परिणाम है कि लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है। यह धारा 140 (5) (पहला भाग) के तहत अंतिम आदेश का पहला परिणाम है। न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर कि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया है धोखाधड़ी के तरीके से, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक में उल्लिखित दूसरा परिणाम आकर्षित किया जाएगा। इसलिए, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए किसी भी परिणाम के लिए, के पहले भाग के अनुसार जांच पर न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश होगा।

धारा 140 (5)। इसलिए, सही व्याख्या पर, धारा 140 (5) के तहत जांच/कार्यवाही के दौरान या उससे पहले भी किसी कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा इस्तीफे पर भी, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही की कोई समाप्ति नहीं होगी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया था। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि किसी दिए गए मामले में, एक लेखा परीक्षक, जिसने वास्तव में धारा के दूसरे परंतुक के तहत किसी भी आगे के परिणाम से बचने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से काम किया है।

140 (5) , धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत किसी भी परिणाम से बचने के लिए इस्तीफा देता है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. जहाँ तक संबंधित लेखा परीक्षकों की ओर से यह निवेदन है कि भले ही धारा 140 (5) न होती, उस मामले में भी कोई भी लेखा परीक्षक धोखाधड़ी, धोखाधड़ी के लिए उकसाने या भारत के पेशेवर संघ से बच नहीं सकता है।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

दुराचार आदि और उस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 132,141,147,245 और 447 पर निर्भरता का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपरोक्त सभी प्रावधान और धारा 140 (5) अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। धारा 140 (5) को एक विशेष उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि एन. सी. एल. टी. द्वारा अंतिम आदेश पारित होने पर, ऐसा लेखा परीक्षक पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य कंपनी में लेखा परीक्षक बनने का पात्र नहीं होगा। इसलिए, केवल इसलिए कि लेखा परीक्षक

किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में अन्य प्रावधानों सहित हटाया जा सकता है, धारा 140 (5) जिसे एक विशेष उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है। इसे मनमाना और/या अति अधिकार नहीं कहा जा सकता है।

9. अब जहाँ तक अधिनियम की धारा 241 (3) पर निर्भरता और यह निवेदन है कि ऐसे मामले में भी जहाँ लेखा परीक्षक इस्तीफा देता है,

संबंधित लेखा परीक्षक के खिलाफ अधिनियम की धारा 241 (3) के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इसलिए अधिनियम की धारा 241 (3) के अनुसार कार्यवाही से वही परिणाम सामने आएगा और लेखा परीक्षक को किसी अन्य संबंधित कार्यालय में नियुक्त किए जाने के लिए 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं' माना जाएगा।

किसी भी कंपनी के आचरण और प्रबंधन के संबंध में, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 241 (3) संबंधित कंपनी के बारे में बात करती है न कि किसी अन्य कंपनी के बारे में। अधिनियम की धारा 241 (3) डब्ल्यू. ई. एफ. 14.08.2019 पेश की गई है जो

केंद्र सरकार यह घोषित करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करेगी कि व्यक्ति अधिनियम की धारा 241 (3) में उल्लिखित "उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं हैं"

किसी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से जुड़े निदेशक या किसी अन्य कार्यालय का पद धारण करना। अधिनियम की धारा 241 (3) को धारा 243 (1 ए) और धारा 243 (2) के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि संदर्भ

विशेष रूप से अधिनियम की धारा 241 (3) में "किसी भी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य कार्यालय" का अर्थ है प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशक जैसे प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के समान और लेखा परीक्षक नहीं। अधिनियम की धारा 241 (3) में उपयोग किए गए शब्द "कंपनी का आचरण और प्रबंधन" हैं। अधिनियम, 2013 की योजना के अनुसार, विशेष रूप से अध्याय X के अनुसार, लेखा परीक्षक खातों के एक स्वतंत्र परीक्षक के रूप में कार्य करता है और उसे कंपनी के संचालन और प्रबंधन में एक पद धारण करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत करना कि अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत जो हासिल किया जा सकता है, वह लेखा परीक्षक के इस्तीफा देने के बाद भी धारा 241 (3) द्वारा हासिल किया जा सकता है, इसमें कोई सार नहीं है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 140 (5) में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि "के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना

इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान। इसलिए, धारा 140 (5) को अधिनियमित करते समय विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट है और धारा के तहत न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियां।

140 (5) कंपनी अधिनियम, 2013 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा। इसलिए, अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 140 (5) के तहत इस आरोप पर लेखा परीक्षक के खिलाफ अंतिम आदेश पारित करने की शक्तियां निहित हैं कि कंपनी के ऐसे लेखा परीक्षक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी से काम किया है।

11. ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय ने लेखा परीक्षकों-बी. एस. आर. एंड डेलॉयट और अन्य के इस्तीफे पर यह निर्णय देने में भौतिक रूप से गलती की है।

नए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, धारा 140 (5) के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने में गलती की है, जिसके द्वारा एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बावजूद, धारा 140 (5) के तहत जांच/कार्यवाही बनाए रखी जाएगी और/या जारी रखी जाएगी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेखा परीक्षकों के बाद के इस्तीफे के बावजूद और/या धारा 140 (5) के दूसरे परन्तुक के उद्देश्य से भी एक लेखा परीक्षक के इस्तीफे के बावजूद, धारा 140 (5) (पहला भाग) के तहत जांच/कार्यवाही/आवेदन बनाए रखने योग्य और जारी रहेगा और एन. सी. एल. टी. द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने पर, जैसा कि धारा 140 (5) में प्रदान किया गया है, परिणाम धारा 140 (5) के दूसरे परन्तुक के तहत प्रदान किया गया है।

इसका पालन करेंगे। चूंकि न तो एन. सी. एल. टी. और न ही उच्च न्यायालय ने संबंधित लेखा परीक्षकों के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष पर ध्यान दिया है और एन. सी. एल. टी. और उच्च न्यायालय का निर्णय इसकी स्थिरता पर है।

लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बाद धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही, हम लेखा परीक्षकों के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष पर कुछ भी विचार करने से बचते हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा की गई धारा 140 (5) के तहत एक आवेदन में गुण-दोष पर न्यायाधिकरण द्वारा धोखाधड़ी आदि के आरोपों पर विचार किया जाना बाकी है।

12. अब जहां तक अधिनियम की धारा 140 (5) की शक्तियों को चुनौती देने का संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि

अन्यथा गुण-दोष पर भी, जब कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के पास है भारतीय उच्च न्यायालय संघ और एक अन्य बनाम द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

धारा 140 (5) की संवैधानिक वैधता/अधिकार पर, हमारी राय है कि धारा 140 (5) को अत्यधिक और/या स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि तर्क दिया गया है। धारा 140 (5) की संवैधानिकता/अधिकार पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि धारा 140 (5) अत्यधिक और मनमाना है क्योंकि यह धोखाधड़ी के गंभीर अपराध के निर्धारण के लिए एन. सी. एल. टी. को निर्देशित और अनियंत्रित शक्तियां प्रदान करती है और

13. अब जहाँ तक एक अन्य निवेदन की बात है कि धारा 140 (5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और निदेशकों, प्रबंधन आदि जैसे समान रूप से रखे गए कथित अपराधियों की तुलना में लेखा परीक्षकों के साथ अनुचित तरीके से भेदभाव करती है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लेखा परीक्षकों की भूमिका को निदेशकों और/या प्रबंधन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लेखा परीक्षक कंपनी के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए उन्हें व्यापक सार्वजनिक हित में और निवेशकों आदि सहित अन्य सभी हितधारकों के लिए कार्य करना पड़ता है। अधिनियम का अध्याय X विशेष रूप से लेखा परीक्षकों के महत्व को देखते हुए "लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों" के लिए है। इसलिए, धारा 140 (5) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और/या उल्लंघनकारी नहीं कहा जा सकता है।

14. अब जहाँ तक यह निवेदन है कि लेखा परीक्षकों और पूरी फर्म की स्वचालित अयोग्यता के रूप में जुर्माना

भागीदारों और वह भी पांच साल की अवधि के लिए किसी अन्य कंपनी का लेखा परीक्षक बनने के लिए अत्यधिक अनुपातहीन है, यह अंततः है विधायिका/संसद को प्रतिबंध प्रदान करने के लिए। संयुक्त और गंभीर दायित्व के सिद्धांत पर, लेखा परीक्षक और भागीदारों सहित पूरी फर्म उत्तरदायी होगी और इसलिए धारा 140 (5) और अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) में उल्लिखित परिणामों के अधीन हो सकती है। जहाँ तक यह निवेदन है कि अयोग्यता नागरिक मृत्यु के समान है और

धारा 140 (5) बी. एस. आर. और उसके भागीदारों के अपने पेशे को जारी रखने के मौलिक अधिकार को बाधित करती है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटी दी गई है, किसी को भी यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि इसके बावजूद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी से कार्य करते हुए, उन्हें जारी रखने का अधिकार था

और/या अपने पेशे को जारी रखें। एक लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी के तरीके से कार्य करना एक बहुत ही गंभीर कदाचार है और इसलिए इस तरह के धोखाधड़ी के कार्य में शामिल होने का आवश्यक परिणाम होगा। फॉलो करें।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, अधिनियम की धारा 140 (5) को विशिष्ट उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया है और

ऊपर उल्लिखित उद्देश्य और वही अधिनियमित किया गया है।

उचित विचार-विमर्श और स्थायी समिति के साथ-साथ संबंधित हितधारकों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद। इसलिए, उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए अधिनियम की धारा 140 (5) को अधिनियमित किया गया है, इसे मनमाना, अत्यधिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

15. अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा धारा 212 (14) के निर्देश को रद्द करने और रद्द करने का संबंध है, यह

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से 212 (14) निर्देश को अलग कर दिया है

दो आधार, पहला, कि मुकदमा चलाने का निर्देश आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट की रिपोर्ट के 30 घंटे के भीतर जारी किया गया था जो दर्शाता है कि

दिमाग का अनुप्रयोग और दूसरा इस आधार पर कि आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट एक अधूरी रिपोर्ट थी क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई थी और इसलिए 212 (14) निर्देश अक्षम था।

15.1 उच्च न्यायालय के तर्क से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 212 (14) के तहत दिए गए निर्देश को दरकिनार कर दिया है और इसे विवेक का उपयोग न करने के रूप में वर्णित किया है क्योंकि यह असंभव था कि लगभग 750 पृष्ठों और 32000 पृष्ठों के अनुलग्नकों की रिपोर्ट हो सकती थी।

30 घंटे के भीतर माना जाता है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेक के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। उपरोक्त निष्कर्ष के साथ, उच्च न्यायालय ने कहा है कि जांच एजेंसी के अनुसार, एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट थी, यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा भी पूछी गई थी।

15.2 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की प्राप्ति के 30 घंटों के भीतर मुकदमा चलाने का निर्देश जारी करना है आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट दर्शाती है कि दिमाग का उपयोग पहले जैसा नहीं था।

यह असंभव है कि लगभग 750 पृष्ठों और 32000 पृष्ठों के अनुलग्नकों की रिपोर्ट पर 30 घंटों में विचार किया जा सकता था, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि मुकदमा चलाने का निर्देश 30 घंटों के भीतर जारी किया गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि दिमाग का उपयोग नहीं किया गया था। अधिकारी द्वारा एक विस्तृत नोट तैयार किया गया था जिसे अंततः अंतिम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था जिसने अंततः निर्णय लिया और मुकदमा चलाने का

निर्देश जारी किया। जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या भारत और ए. एन. डी. एच. वी. का संघ था।

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

मुकदमा चलाने के लिए कोई सामग्री या नहीं और क्या मुकदमा चलाने का निर्देश ठीक से दिया गया था या नहीं। मुकदमे के दौरान, अभियुक्तों को अपना मामला रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अतः उपरोक्त पर

इस आधार पर कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 212 (14) के तहत जारी अभियोजन के निर्देश को रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

अभिलेख पर नहीं रखे जाने का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुकदमा चलाने का अंतिम आदेश अभिलेख पर रखा गया था जिसमें यह कहा गया है कि विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आई. एफ. आई. एन. एस. एफ. आई. ओ. रिपोर्ट को देखा है।

15.3 अब जहाँ तक एक अन्य आधार है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने के निर्देश/मंजूरी को दरकिनार कर दिया गया है, अर्थात्, यह एक अधूरी जांच रिपोर्ट थी और इसलिए इस तरह की अधूरी रिपोर्ट पर।

जांच रिपोर्ट, मुकदमा चलाने के लिए कोई निर्देश/मंजूरी जारी नहीं की जा सकती थी, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय ने ठीक से सराहना नहीं की है कि एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट एक

एस. एफ. आई. ओ. द्वारा आई. एफ. आई. एन. की जाँच पूरी होने पर तैयार की गई रिपोर्ट-जाँच के अधीन कंपनियों में से एक। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 30.09.2018 दिनांकित एक आदेश द्वारा, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा आई. एल. एंड एफ. एस. और इसकी सहायक कंपनियों में एक जांच करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें लगभग 100-160 संस्थाएं शामिल हैं। जहाँ तक आई. एफ. आई. एन. है संबंधित रूप से, यह आई. एल. एंड एफ. एस. समूह और वित्तीय सेवा शाखा की सहायक कंपनियों में से एक थी। केंद्र सरकार की ओर से यह मामला है कि जहां तक एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट का संबंध है, यह आई. एफ. आई. एन. की जांच पूरी होने पर आई. एफ. आई. एन. के संबंध में एक रिकॉर्ड है। केवल इसलिए कि जहां तक आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की अन्य सहायक कंपनियों के संबंध में जांच का संबंध है, वही चल रहा होगा, यह देखने का आधार नहीं हो सकता है कि इस स्तर पर जहां तक आई. एफ. आई. एन. का संबंध है, रिपोर्ट अधूरी थी और जिसके लिए जांच चल रही थी। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त की उचित रूप से सराहना नहीं की है और जहां तक आई. एफ. आई. एन. का संबंध है, रिपोर्ट को एक अंतरिम रिपोर्ट के रूप में गलत तरीके से माना है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एस. एफ. आई. ओ. आई. एफ. आई. एन. रिपोर्ट में ही यह देखा गया है कि आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की जटिल संरचना और संस्थाओं आदि के बीच अंतर-संबंधों के आलोक में, यदि इस अवधि के दौरान आई. एफ. आई. एन. के तहत कोई और उदाहरण या लेनदेन सामने आते हैं।

आई. एल. एंड एफ. एस. की अन्य समूह कंपनियों की जांच, फिर एक आगे की रिपोर्ट दायर की जाएगी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने भौतिक रूप से गलती की है कि आई. एफ. आई. एन. के संबंध में जांच अधूरी है। यह नोट किया जाना आवश्यक है [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि एस. एफ. आई. ओ. ने आई. एफ. आई. एन. की विस्तृत और व्यापक जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हरि शंकरन सहित प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णायक निष्कर्ष हैं जो कई उल्लंघनों, वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन और धोखाधड़ीपूर्ण आचरण की ओर इशारा करते हैं। हम इसे विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभियोजन अभी तक नहीं हुआ है और संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना है। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही धारा 212 (14) के तहत अभियोजन की अनुमति देने और मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के निर्देश के चरण में थी। संबंधित अभियुक्त के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष कंपनी अधिनियम की धारा 447 और आई. पी. सी. के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आदेश दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस स्तर पर और उपरोक्त आधारों पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 212 (14) के तहत निर्देश को दरकिनार करते हुए गलती की है।

निष्कर्ष:

16. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, चुनौती

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) की संवैधानिक वैधता विफल हो जाती है और यह माना जाता है कि धारा 140 (5) न तो भेदभावपूर्ण, मनमाना और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) का उल्लंघन है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 140 (5) के तहत आवेदन/कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने के लिए विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया है कि क्योंकि लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसलिए उसके बाद वह बनाए रखने योग्य नहीं है।

और अलग रख दें। नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने एन. सी. एल. टी. के आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बाद भी, धारा 140 (5) के तहत कार्यवाही बनाए रखने योग्य होगी और इसे रद्द कर दिया जाता है। अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत आवेदन/कार्यवाही को संबंधित लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बाद भी बनाए रखने योग्य माना जाता है और अब एन. सी. एल. टी. इसलिए कानून के अनुसार जांच करने के बाद ऐसे आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करता है और उसके बाद ऐसे अंतिम आदेश के आधार पर, धारा 140 (5) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए आगे के परिणाम सामने आएंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने संबंधित लेखा परीक्षकों के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और यह अंततः एन. सी. एल. टी./न्यायाधिकरण पर है कि वह अधिनियम, 2013 की धारा 140 (5) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दायर आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करे।

17. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और भारत का संघ और अन्य V.

डीलोइट हैस्कंस एंड सेल्स एलएलपी [एम. आर. शाह, जे.]

भारत संघ द्वारा एस. एफ. आई. ओ. को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (14) दिनांक 1 के तहत दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। विशेष अदालत (कंपनी अधिनियम) और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई की फाइल पर एस. एफ. आई. ओ. द्वारा आपराधिक शिकायत सी. सी. No.20/2019 के माध्यम से दर्ज किए गए अभियोजन को रद्द करने और खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है। अब उक्त आपराधिक शिकायत सी. सी. सं. 20/2019 को संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

18. तदनुसार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत संघ द्वारा दायर अपीलें, अर्थात् , आपराधिक अपील सं. 2305-2307 / 2022 ; 2302-2303 / 2022 ; और 2300/2022 की अनुमति है और आपराधिक अपील संख्या 2298/2022 , 2299/2022 और 2304/2022, साथ ही, डेलॉयट और उसके भागीदारों द्वारा दायर सिविल अपील Nos.793/2022; 801/2022 और 877/2022 को भी खारिज कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस

(सहायक: शुभांशु दास, एलसीआरए)